वर्ष 12 • अंक 255 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 13 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

सोना लुढ़का तो गहनों की मांग बढ़ी

आदि गोदरेज पृष्ठ 3

गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलीं चार नई परियोजनाएं

डॉलर रु. 70.80 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.80 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 37778 ▲ 137 रुपये | सेंसेक्स 40581.70 ▲ 169.10 | निफ्टी 11971.80 ▲ 61.60 | निफ्टी फ्यूचर्स 12028.70 ▲ 56.90 | ब्रेंट क्रूड 65.50 डॉलर ▲ 0.30 डॉलर

एक नज़र

अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो घटेगी रेटिंग: एसऐंडपी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो वह इसकी रेटिंग में कमी कर सकती है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही एजेंसी ने भारत की रेटिंग और परिदृश्य पर अपना रुख बरकरार रखा था। एक दूसरी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक महीने पहले भारत के लिए सॉवरिन क्रेडिट में कमी कर दी थी। एसऐंडपी ने इस समय भारत को स्थिर परिदृश्य के साथ 'बीबीबी' रेटिंग दे रखी है। पृष्ठ 4

पहले दिन 50 प्रतिशत चढ़ा उज्जीवन फाइनैंस

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक (एसएफबी) का शेयर गुरुवार को कारोबार के पहले दिन करीब 70 प्रतिशत उछल गया। पिछले सप्ताह कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में शेयरों की खासी मांग दिखी थी। शेयर पहले दिन अपने निर्गम मूल्य 37 रुपये से 50 प्रतिशत (18.30 रुपये) उछलकर 55.30 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई पर कारोबार के दौरान शेयर 62.80 के ऊंचे और 53 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा था।

अरामको बनी 2,000 अरब डॉलर की कंपनी

सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने शेयर बाजार में कारोबार के दूसरे ही दिन गुरुवार को 2,000 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया। इस तरह, यह इतना बड़ा बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अरामको को पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी होने का श्रेय हासिल हो चुका है। दूसरे स्थान पर अमेरिका की कंपनी ऐपल है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1,190 अरब डॉलर है।

जीएसटी चोरी पर अंकुश के लिए लॉटरी योजना!

विक्रेता से बिल की कॉपी मांगना अब ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ग्राहकों में बिल लेने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने पर विचार कर रही है। राजस्व संवर्द्धन अधिकारियों की समिति इस दिशा में काम कर रही है, जिसका मकसद जीएसटी संग्रह बढ़ाना है। इस प्रस्ताव पर 18 दिसंबर को जीएसटी परिषद में विचार हो सकता है। पृष्ठ 4

आज का सवाल

क्या बॉन्ड में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाना उचित कदम होगा

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आईबीसी में संशोधन से समाधान प्रक्रिया में आएगी तेजी?	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

एफपीआई निवेश सीमा बढ़ेगी!

सरकारी बॉन्ड में बढ़ेगी एफपीआई निवेश सीमा, वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में होगा शामिल

हंसिनी कार्तिक और अनूप रॉय
मुंबई, 12 दिसंबर

- मौजूदा **6** फीसदी की सीमा बढ़ाकर **10** फीसदी करने पर विचार
- मुद्रा जोखिम को लेकर आरबीआई चिंतित
- स्थानीय बॉन्डों की वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में होगी पहुंच
- एएसआईएफएमए और पीडब्ल्यूसी इस मामले में कर रही है मदद
- सीमा बढ़ाने की घोषणा आगामी आम बजट में की जा सकती है

केंद्र सरकार सरकारी बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निवेश सीमा मौजूदा 6 फीसदी से बढ़ाकर कम से कम 10 फीसदी करने पर विचार कर रही है। मामले के जानकार सूत्रों के अनुसार इस कदम का मकसद स्थानीय बॉन्डों को वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल करना है।

दीर्घावधि निवेशकों सहित एफपीआई अभी सरकारी बॉन्डों में 3.61 लाख करोड़ रुपये तक निवेश कर सकते हैं, इनमें से 12 दिसंबर तक इन्होंने 2.16 लाख करोड़ रुपये निवेश किया है। लेकिन एफपीआई को कुल आवंटित शेयर वैश्विक बॉन्ड सूचकांक जैसे कि जेपी मॉर्गन, ब्लूमबर्ग-बार्कली में शामिल कराने के लिए अपर्याप्त है।

सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग को इसके बारे में पहले ही सूचित कर चुका है। आमतौर पर इन सूचकांकों के लिए पात्रता की खातिर कुल जारी शेयरों में से कम से कम 15 से 20 फीसदी विदेशी निवेशकों को दिए जाने की शर्त है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसमें पर्याप्त तरलता है और साथ ही निवेश जोखिम को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का भी विकल्प उपलब्ध होता है।

सूत्रों ने कहा कि भारत की योजना सॉवरिन बॉन्ड को शामिल कराने की हो सकती है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसके पक्ष में नहीं है। केंद्रीय बैंक नहीं चाहता है कि किसी तरह की मुद्रा जोखिम की स्थिति बने। हालांकि सूचकांक में शामिल होने वाले बॉन्ड अपने आप अर्द्ध-सॉवरिन बॉन्ड हो जाते हैं क्योंकि इन बॉन्डों में कोई भी निवेशक निवेश कर सकता है या उसे बेच सकता है।

आरबीआई सरकारी बॉन्डों में एफपीआई की निवेश सीमा को दोगुना से अधिक 15 फीसदी करने के लिए तैयार नहीं है जबकि सूचकांक में शामिल होने की यह पूर्व शर्त है। लेकिन केंद्रीय बैंक चाहता है कि सरकार इस दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़े और पहले यह देखे कि मुद्रा जोखिम को किस तरह से कवर किया जा सकता है। ऐसे में अगर 10 फीसदी की सीमा घोषित की जाती है तो इसे बढ़ाने के लिए आगे एक या दो साल और इंतजार करना पड़ सकता है। 10 फीसदी की सीमा का ऐलान संभवत: आम बजट में किया जा सकता है।

वित्तीय सूचना फर्म ब्लूमबर्ग एलपी इस मामले में वित्त मंत्रालय की मदद कर रही है और अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे एशिया सिक्योरिटीज इंडस्ट्री ऐंड फाइनैंशियल मार्केट्स एसोसिएशन (एएसआईएफएमए) मुद्रा जोखिम, कर मसलों और अन्य संभावित अड़चनों को दूर करने के उपायों पर काम कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में भारत में एएसआईएफएमए की मदद पीडब्ल्यूसी कर रही है।

जब कोई सॉवरिन बॉन्ड वैश्विक सूचकांक में शामिल होता है तो उस देश में निवेश कई गुना बढ़ जाता है। ब्लूमबर्ग के भारत में अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने कहा, 'वैश्विक बेंचमार्क सूचकांक में शामिल होने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 50 से 125 अरब डॉलर नया निवेश आ सकता है।'

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कमजोर मांग के बीच सब्जियों ने बढ़ाई महंगाई

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

आईआईपी गिरा, मुद्रास्फीति बढ़ी

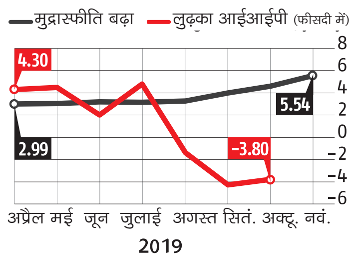

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

खाने पीने की वस्तुओं खासकर सब्जियों के दाम चढ़ने से नवंबर में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई जो 40 महीने का उच्च स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 4.62 फीसदी और पिछले साल नवंबर में 2.33 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में सबसे ज्यादा सब्जियों के दाम में 35.99 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर में यह 26.10 प्रतिशत थी। इसी तरह नवंबर में मोटे अनाज की मुद्रास्फीति बढ़कर 3.71 प्रतिशत पर पहुंच गई। मांस और मछली की मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 9.38 प्रतिशत बढ़ी। अंडे में भी नवंबर में 6.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। दालों और उससे जुड़े उत्पादों की मुद्रास्फीति माह के दौरान बढ़कर 13.94 प्रतिशत रही। प्याज सहित सब्जियों की आपूर्ति में प्रभावित होने से महंगाई बढ़ी।

आईआईपी में लगातार तीसरे महीने गिरावट

बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में अक्टूबर महीने में 3.8 फीसदी की गिरावट आई। यह लगातार तीसरा महीना है जबकि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। सितंबर में आईआईपी में 4.3 फीसदी की गिरावट आई थी जो आठ साल का उच्च स्तर है। आईआईपी में 78 फीसदी भारांश रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 2.1 फीसदी की गिरावट आई जबकि सितंबर में इसमें 3.9 फीसदी की गिरावट आई थी। आईआईपी के आंकड़ों से पता चलता है कि वाहन क्षेत्र में नरमी बनी हुई है।

असम में भारी प्रदर्शन, त्रिपुरा बंद

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को और उग्र हो गया। गुवाहाटी में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। त्रिपुरा में कांग्रेस के 24 घंटे के बंद के आह्वान पर स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहे तथा सड़कों से वाहन नदारद रहे। असम से आने-जाने वाली कई ट्रेनें और उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं।

इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने गुरुवार से शुरू होने वाला भारत का अपना तीन दिवसीय दौरा रद्द कर दिया। ढाका में जारी एक बयान में मोमिन ने कहा कि उन्हें अपनी व्यस्तताओं के चलते भारत की यात्रा रद्द करनी पड़ी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि सीएबी के पारित होने से पैदा हुए हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द की है।

गुवाहाटी में 15 से 17 दिसंबर तक होने वाली भारत-जापान शिखर वार्ता पर भी इस संकट के बादल छाए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बारे में उसके पास साझा करने के लिए कोई अपडेट नहीं है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस रैंक में कुछ बदलाव किए हैं। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हटा दिया गया है और उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) मुकेश अग्रवाल का स्थानांतरण एडीजीपी (सीआईडी) के रूप में किया गया और जी पी सिंह को उनका प्रभार दिया गया है।

पृष्ठ 14

बड़े निवेशकों से येस बैंक की बात

सुब्रत पांडा और हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 12 दिसंबर

- रवनीत गिल ने खारिज की जबरन विलय की अटकलें
- यूरोपीय निवेशकों से चल रही है बातचीत
- 1.75 अरब डॉलर जुटाने के लिए बेचेगी 20-25 फीसदी हिस्सेदारी
- बाध्यकारी समझौते के बाद होगा नामों का खुलासा

येस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी रवनीत गिल ने बैंक पर जबरन विलय थोपने की खबरों को खारिज करते हुए आज भरोसा जताया कि 1.75 अरब डॉलर पूंजी जुट जाएगी।

गिल ने कहा, 'फाइनैंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने बैंक में दिलचस्पी दिखाई है।' उन्होंने कहा कि बातचीत अग्रिम दौर में पहुंच चुकी है और उनके साथ बाध्यकारी समझौता होने के बाद ही बैंक निवेशकों के नामों का खुलासा करेगा।

सूत्रों के मुताबिक चार से पांच वित्तीय संस्थाओं ने येस बैंक में दिलचस्पी दिखाई है और उनमें से एक निवेशक 10 फीसदी तक हिस्सेदारी ले सकता है। दूसरे निवेशकों में से हरेक के 4 से 5 फीसदी हिस्सेदारी लेने की संभावना है। गिल ने कहा कि जिन वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंक की बातचीत चल रही है, वे प्रतिष्ठित निवेशक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की कसौटी पर खरे उतरेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि लंदन की कंपनी साइटैक्स होल्डिंग्स ऐंड साइटैक्स इनवेस्टमेंट ग्रुप ने बैंक में 50 करोड़ डॉलर निवेश करने का वादा किया है और इसे भी नियामकीय मंजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें किसी तरह की नियामकीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।'

जीएमआर समूह और इरविन सिंह बराइच के बैंक में निवेश करने की चर्चा है। लेकिन गिल ने स्पष्ट किया कि पूंजी जुटाने के इस दौर में इस श्रेणी के निवेशकों के शामिल होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, 'जहां तक भारतीय निवेशकों और पारिवारिक समूहों का संबंध है, हमने उन्हें बताया है कि इस दौर में हम संस्थागत मार्ग से पूंजी जुटाएंगे।' मीडिया खबरों के मुताबिक कनाडा के बराइच ने येस बैंक में 1.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सिंह की पेशकश बैंक के लिए अब तक की सबसे बड़ी पेशकश है।

येस बैंक को 23 दिसंबर तक एटी-1 बॉन्ड के लिए 300 करोड़ रुपये की देनदारी का भुगतान करना है और बैंक को उम्मीद है कि वह समय पर इसका भुगतान कर देगा। पूंजी संबंधी समस्याओं के इतर बैंक को दिसंबर तिमाही के नतीजों में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की कसौटी पर भी खरा उतरना है।

वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में बैंक का 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज एनपीए बन चुका है। सितंबर, 2019 तक बैंक ने 30 हजार करोड़ रुपये के ऋण को दबावग्रस्त करार दिया है। ये निवेश से नीचे की श्रेणी में आते हैं। यह पूछने पर कि क्या तीसरी तिमाही में एनपीए या दबावग्रस्त परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, गिल ने कहा कि हाल फिलहाल कोई नई मुसीबत नहीं है और इन दोनों मानकों में से कोई भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए।

बैंक ने पिछली तिमाही में पात्र संस्थागत निवेशकों से 1,930 करोड़ रुपये जुटाए थे। वित्त वर्ष 2019 की मार्च तिमाही में बैंक का कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात 8 फीसदी था जो इस साल दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.7 फीसदी हो गया। इससे बैंक को अपने बकाया बहीखाते को दुरुस्त करने में मदद मिली।

बैंक को उम्मीद है कि 10 हजार करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का जल्द ही समाधान होगा जिससे उसे कुछ पूंजी मिलेगी।

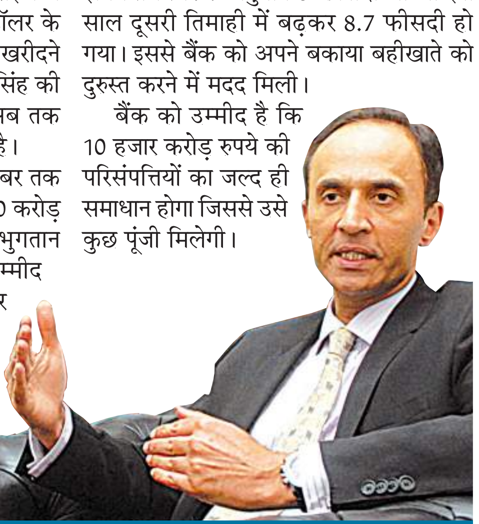

रवनीत गिल, एमडी व सीईओ, येस बैंक

खबरों में रहे स्टॉक

गोदरेज प्रॉपर्टीज

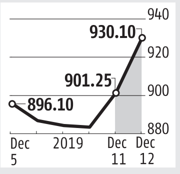

मुंबई क्षेत्र, बेंगलूरु में चार नई परियोजनाएं शुरू

₹ 901.25 पिछला बंद भाव
₹ 930.10 आज का बंद भाव
▲3.20 %

टाटा मोटर्स

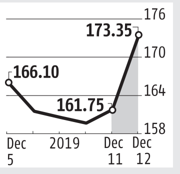

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 161.75 पिछला बंद भाव
₹ 173.35 आज का बंद भाव
▲7.17 %

आवास फाइनैंसर्स

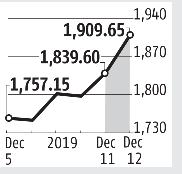

एनसीडी के जरिये 460 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

₹ 1,839.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,909.65 आज का बंद भाव
▲3.81 %

मणप्पुरम फाइनैंस

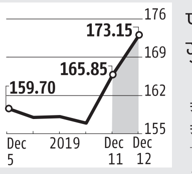

पूंजीकरण और परिसंपत्ति गुणवत्ता दमदार

₹ 165.85 पिछला बंद भाव
₹ 173.15 आज का बंद भाव
▲4.40 %

इन्फोसिस

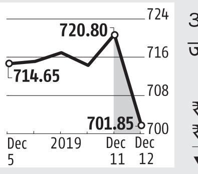

अमेरिका में गलत वित्तीय जानकारी के लिए मुकदमा

₹ 720.80 पिछला बंद भाव
₹ 701.85 आज का बंद भाव
▼2.63 %

संक्षेप में

हीरो मोटोकॉर्प फरवरी तक 10 बीएस6 मॉडल उतारेगी

हीरो मोटोकॉर्प की योजना अगले डेढ़-दो महीने में करीब 10 बीएस6 वाहन उतारने की है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी अगले साल फरवरी तक करीब इन मॉडलों को उतारेगी। इनमें उसके पांच सबसे अधिक बिकने वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि कंपनी की योजना जयपुर के अपने शोध एवं विकास केंद्र में एक कार्यक्रम में फरवरी, 2020 में इन वाहनों के अद्यतन मॉडलों का प्रदर्शन करने की है। कंपनी ने बीएस6 मानक की समयसीमा 1 अप्रैल 2020 से पहले ही अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को नए मानकों के अनुरूप अद्यतन कर लिया है। *भाषा*

रिलायंस की इकाई ने नाऊ फ्लोट्स में ली हिस्सेदारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने गुरुवार को कहा कि उसकी सहायक इकाई ने नाऊफ्लोट्स टेक्नोलॉजिज में 85 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह सौदा 141.63 करोड़ रुपये का है। इस हिस्सेदारी खरीद का मकसद समूह के डिजिटल और नई वाणिज्यिक पहल को मजबूत करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज दी सूचना में कहा, आरआईएल की पूर्ण सहायक इकाई रिलायंस स्ट्रैटजिक बिजनेस वेंचर्स लि. (आरएसबीवीएल) ने 141,63,78,822 रुपये में नाऊफ्लोट्स टेक्नोलॉजिज में 85 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। *भाषा*

टाटा स्टील करेगी यूरोप में छंटनी

विश्लेषकों ने कहा, मौजूदा हालात में कंपनी के पास छंटनी के अलावा विकल्प नहीं

अदिति दिवेकर
मुंबई, 12 दिसंबर

टाटा स्टील अपने यूरोपीय परिचालन में करीब 3,000 लोगों की छंटनी कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यह भले ही सख्त कदम दिख रहा हो लेकिन मौजूदा बाजार परिदृश्य में छंटनी के अलावा कंपनी के पास अधिक विकल्प मौजूद नहीं है।

विदेशी ब्रोकरेज के एक विश्लेषक ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'टाटा स्टील यूके संयंत्र की एबिटा नकारात्मक है। ऐसे में भारी छंटनी के जरिये कर्मचारी लागत घटाना और अंतत: उस संयंत्र को बंद करना बिल्कुल सही लगता है।'

हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कितने लोगों की छंटनी की जाएगी। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि लागत में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए बड़ी तादाद में छंटनी करने की जरूरत है। टाटा स्टील यूरोप की उत्पादन क्षमता फिलहाल 1.25 करोड़ टन है और उसके कर्मचारियों की संख्या करीब 21,000 है।

इसमें से पोर्ट टालबोट (ब्रिटेन) की क्षमता करीब 50 लाख टन है और वहां 8,500 लोग कार्यरत हैं जबकि नीदरलैंड के संयंत्र की क्षमता करीब 75 लाख टन है। नीदरलैंड परिचालन में फिलहाल 10,000 लोग कार्यरत हैं।

यूरोपीयन स्टील एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में यूरोपीय संघ में इस्पात के उत्पादन में 8.7 फीसदी की गिरावट आई जहां कंपनियों ने इस साल उत्पादन में कम से कम 1.5 करोड़ टन की कटौती करने की घोषणा की है। साथ ही अक्टूबर में कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में सालाना आधार पर 2.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। कमजोर आर्थिक परिदृश्य में मिश्रधातु के उत्पादन में कमी आई है।

लागत घटाने की कवायद

- अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कितने लोगों की छंटनी की जाएगी
- टाटा स्टील यूके संयंत्र की एबिटा नकारात्मक है और ऐसे में लागत घटाना जरूरी है
- पोर्ट टालबोट (ब्रिटेन) की क्षमता करीब 50 लाख टन है और वहां 8,500 लोग कार्यरत हैं
- नीदरलैंड के संयंत्र की क्षमता करीब 75 लाख टन है जहां 10,000 लोग कार्यरत हैं

यूरोपीय क्षेत्र में टाटा स्टील की प्रतिस्पर्धा आर्सेलर मित्तल और टिसेनक्रप जैसी बड़ी कंपनियों से है।

विदेशी ब्रोकरेज के विश्लेषक ने कहा, 'टाटा स्टील सख्त बाजार परिदृश्य से भी जूझ रही है लेकिन उसकी एबिटा लगातार सकारात्मक बनी हुई है। इसलिए टाटा स्टील को लागत पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी। जो करने की जरूरत है उसे किया जाना चाहिए।'

यूरोपीय इस्पात कंपनियों को विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती से जूझना पड़ रहा है। उस क्षेत्र में वाहनों की खपत में भी गिरावट आई है जिसका असर इस्पात कंपनियों पर भी पड़ा है।

विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल के लिए भी कारोबार कठिन हो गया है। यूरोप में उसके कई संयंत्र बंद हो चुके हैं अथवा उत्पादन में कटौती की जा रही है।

कोरस के अधिग्रहण के बाद से ही टाटा स्टील के कर्मचारी लागत उसके कुल खर्च के प्रतिशत में काफी अधिक दिख रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018 में कुल खर्च में कर्मचारी लागत 20.5 फीसदी रही जो वित्त वर्ष 2009 में 13.5 फीसदी पर सबसे कम थी।

रिलायंस के आने से सस्ती होगी बीमारियों की जांच!

सोहिनी दास
मुंबई, 12 दिसंबर

रिलायंस लाइफ साइंसेज (आरएलएस) भारत के 9.6 अरब डॉलर के डायग्नोस्टिक्स उद्योग में उतरने की योजना बना रही है। इस बाजार में पहले से ही मौजूद कंपनियों का कहना है कि रिलायंस के आने से इस क्षेत्र में कीमतें घटेंगी जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी।

डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी थायरोकेयर के प्रवर्तक, चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी ए वेलुमणि का मानना है कि डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र में रिलायंस के आने से उसके दूरसंचार कारोबार जियो की तरह मूल्य संबंधी उथल-पुथल मच सकता है। उन्होंने कहा, 'यदि वे कीमतें घटाएंगे तो अन्य प्रयोगशालाएं भी उसका अनुकरण करेंगी। इससे निश्चित तौर पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी।'

वेलुमणि ने कहा कि फिलहाल करीब 95 फीसदी प्रयोगशालाएं कम क्षमता पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक्स उद्योग में क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बड़ी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने और रोगियों की संख्या बढ़ने से अंतत: उद्योग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के दौरान इस उद्योग का पूरी तरह कायापलट हो जाएगा। थायरोकेयर और आरएलएस ने डीएनए प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षण सेवाओं की पेशकश करने के लिए 2003 में करार किया था।

गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 1 लाख डायग्नोस्टिक्स प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से महज 1,076 प्रयोगशालाएं ही एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। पैथोलॉजी टेस्ट की वर्तमान औसत लागत 280 से 350 रुपये के दायरे में है। बाजार में पैथोलॉजी टेस्ट की हिस्सेदारी करीब 56 फीसदी है जबकि शेष हिस्सेदारी रेडियोलॉजी टेस्ट की है।

अगले पांच वर्षों के दौरान इस बाजार की वृद्धि दर 11 फीसदी रहने की उम्मीद है और उसे मुख्य तौर पर रक्षात्मक टेस्ट से रफ्तार मिलेगी। फिलहाल कुल बाजार में रक्षात्मक टेस्ट की हिस्सेदारी 10 फीसदी से कम है और उसमें 20 फीसदी सीएजीआर के साथ वृद्धि हो रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है, 'सरकार रक्षात्मक टेस्ट के लिए प्रोत्साहन दे रही है और ऐसे में हम समझते हैं कि यह क्षेत्र 27 फीसदी सीएजीआर के साथ वृद्धि कर सकता है।'

बाजार में स्थापित कंपनियों का मानना है कि बड़ी कंपनियों के आने से बढ़ेगी संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी

रिलायंस लाइफ साइंसेज को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। सूत्रों ने संकेत दिया कि कंपनी डायग्नोस्टिक क्षेत्र में उतरने की संभावनाएं तलाश रही है लेकिन उसने अभी अपने कारोबारी मॉडल को अंतिम रूप नहीं दिया है।

मुंबई के एक डायग्नोटिक क्लीनिक श्रृंखला के मालिक ने कहा कि रिलायंस यदि छोटे-मोटे क्लीनिक को अपना साझेदार बनाएगी और उन्हें अपना ब्रांड एवं केंद्रीकृत परीक्षण सुविधा मुहैया कराएगी तो गुणवत्ता को बरकरार रखना कठिन होगा।

सीएलएसए ने कहा है कि भारत में डायग्नोस्टिक्स बाजार काफी असंगठित है और उसमें संगठित डायग्नोटिक श्रृंखलाओं की हिस्सेदारी महज 16 फीसदी है। जबकि 37 फीसदी हिस्सेदारी अस्पताल आधारित केंद्रों की और 47 फीसदी हिस्सेदारी एकल केंद्रों की है। इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में डॉ लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर और एसआरएल डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं।

वोडा आइडिया के बंद होने से एयरटेल को होगा सबसे अधिक फायदा

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

यदि वोडाफोन आइडिया देश में अपना कारोबार बंद करने का निर्णय लेती है तो उसका सबसे अधिक फायदा भारती एयरटेल को होगा। पिछले सप्ताह कुमार मंगलम बिड़ला ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सरकार से यदि कोई राहत न मिली तो आइडिया और वोडाफोन के संयुक्त उद्यम वोडाफोन आइडिया का परिचालन बंद करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत कंपनी को तीन महीने के भीतर 44,150 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करना है।

वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 31.1 करोड़ है जिसमें 7.3 फीसदी पोस्टपेड ग्राहक हैं। यह पोस्टपेड ग्राहकों के बीच सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। विश्लेषकों के अनुसार, कंपनी के कुल राजस्व में इन ग्राहकों का योगदान करीब 20 फीसदी है।

एयरटेल के करीब 5.6 फीसदी ग्राहकों के पास पोस्टपेड कनेक्शन हैं और कंपनी ने इस श्रेणी में सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए एक रणनीति तैयार की है। ऐसे में यदि वोडाफोन आइडिया अपनी दुकान बंद करती है तो अधिक एआरपीयू (प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व) वाले अधिकतर ग्राहक एयरटेल की ओर रुख करेंगे क्योंकि रिलायंस जियो उसकी तरह पोस्टपेड के लिए व्यापक पेशकश नहीं करती है और जियो मुख्य तौर पर प्रीपेड बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पोस्टपेड श्रेणी में जियो की एकमात्र पेशकश (199 रुपये) है जिसका उसके कुल ग्राहकों में महज 1 फीसदी हिस्सेदारी है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के अधिकतर ग्राहक 2जी फोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ ही ग्राहक डेटा का उपयोग करते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पास करीब 20 करोड़ 2जी ग्राहक हैं जिसमें से महज 3.8 करोड़ ग्राहक ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं।

- **वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 31.1 करोड़ है जिसमें 7.3 फीसदी पोस्टपेड ग्राहक हैं**
- **एयरटेल के करीब 5.6 फीसदी ग्राहकों के पास पोस्टपेड कनेक्शन हैं**
- **वोडाफोन आइडिया के करीब 20 करोड़ 2जी ग्राहक हैं जिसमें से महज 3.8 करोड़ ग्राहक ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं**
- **जियो के पास केवल 4जी नेटवर्क है**

विश्लेषकों का कहना है कि एयरटेल के लिए इन ग्राहकों को आकर्षित करना आसान रहेगा क्योंकि वह हैंडसेट अथवा सिमकार्ड बदले बिना उन ग्राहकों को अपने 2जी नेटवर्क पर स्थानांतरित कर सकती है। दूसरी ओर, जियो के पास केवल 4जी नेटवर्क है। जियो की चुनौती शुल्क दरों को लेकर भी होगी जो 15 से 40 फीसदी तक अधिक हो सकती है और ऐसे में 2जी ग्राहक उसकी ओर जाने से पहले सोचेंगे।

गोल्डमैन सैक्स ने एक हालिया बैठक में कहा था कि चेयरमैन सुनील मित्तल के नेतृत्व में भारती एयरटेल आत्म विश्वास से भरी है। उसने कहा था कि कंपनी को विश्वास था कि उद्योग में बाजार के नए सिरे से आवंटन की सूरत में एयरटेल 50 फीसदी बढ़ी हुई हिस्सेदारी हासिल करेगी। साथ ही बढ़त वाले राजस्व का एबिटा मार्जिन काफी अधिक हो सकता है।

यदि ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया के बंद होने पर एयरटेल 15 करोड़ अतिरिक्त ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इससे एयरटेल के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 42.9 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

इतना ही नहीं, शुल्क दरों में भी वृद्धि के साथ ये पोस्टपेड ग्राहक आएंगे जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इससे एयरटेल को अपना एआरपीयू को कुछ तिमाहियों में 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने में मदद मिलेगी।

बहरहाल, वोडाफोन आइडिया के बंद होने से जियो को भी फायदा होगा क्योंकि जो ग्राहक एयरटेल की ओर रुख नहीं करेंगे वे जियो के पास जाएंगे। इससे मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी को 50 करोड़ ग्राहकों का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। जियो के ग्राहकों की संख्या फिलहाल 35 करोड़ है।

सुधार की उम्मीद में बाजार झेल गया झटका

समी मोडक
मुंबई, 12 दिसंबर

कमजोर आर्थिक वृद्धि के बावजूद बाजार अपनी रफ्तार लगातार बरकरार रख रहा है। सितंबर में समाप्त तीन महीने की अवधि के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जो मार्च 2013 के बाद सबसे सुस्त रफ्तार है। हालांकि बाजार जीडीपी के इस झटके से काफी हद तक अप्रभावित रहा।

कमजोर डीडीपी वृद्धि के बावजूद बाजार की रफ्तार बरकरार है। ऐसे में बाजार को कहां से उम्मीद दिख रही है? वर्ष 2020 में सुधार एवं आय वृद्धि की उम्मीद, कॉरपोरेट कर में अचानक की गई कटौती और आसान वैश्विक मौद्रिक नीतियों के मद्देनजर दमदार विदेशी निवेश जैसे कारणों से बाजार का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने जीडीपी के झटके को सहन कर लिया।

हालांकि जीडीपी के आंकड़े दो महीने के अंतराल पर जारी किए गए हैं लेकिन बाजार की नजर हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर होती है। अधिकतर अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक स्थिति और कॉरपोरेट आय में अगले साल तक तेजी आएगी। भारत में गोल्डमैन सैक्स की मुख्य अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 बेहतर रहेगा और वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 अच्छा रहेगा और इसके पांच कारण हैं।' मिश्रा ने कहा, 'पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। दूसरा, दरों में कटौती के बाद घरेलू राजकोषीय स्थिति लगातार सुधर रही है। तीसरा, राजकोषीय प्रोत्साहन सकारात्मक रहने की उम्मीद है। चौथा, तमाम सुधारों के बाद आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर हो रही हैं। पांचवां, आर्थिक स्थिरता के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं।'

अमेरिका के इस निवेश बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 6.6 फीसदी जीडीपी वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है। साथ ही उसने उम्मीद जताई है कि कैलेंडर वर्ष 2020 में कॉरपोरेट आय में करीब 16 फीसदी की वृद्धि होगी जो 20 फीसदी के अनुमान से थोड़ा कम है।

बॉन्ड में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाने की तैयारी

पृष्ठ 1 का शेष...

सूचकांक में बने रहने के लिए सरकार को हमेशा सख्त नियमों का पालन करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बॉन्ड के लिए उसके पास पर्याप्त तरलता है ताकि बाजार में उसकी मुक्त खरीद-बिक्री हो सके। हालांकि सूचकांक इसमें निवेश को हेज करने के लिए समुचित साधन प्रदान करना सुनिश्चित करता है लेकिन घरेलू स्तर पर भी उन्नत डेरिवेटिव्स बाजार की जरूरत होती है। आरबीआई आईएफएससी में वैश्विक डेरिवेटिव की रुपये में खरीद-बिक्री शुरू करने का प्रयास कर रहा है।

अमेरिका की हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइकल ब्लूमबर्ग ने भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश को सुदृढ़ बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। इस साझेदारी का लक्ष्य भारत के सकल घरेलू उत्पादों को 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर करना है। इसके लिए भारत की योजना बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ डॉलर निवेश करने की है। इस निवेश के लिए सरकार को वैश्विक फंड की जरूरत है क्योंकि फंसे कर्ज की वजह से स्थानीय बैंकों पर पहले से ही दबाव है।

निवेशक ब्लूमबर्ग की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे, वहीं ब्लूमबर्ग सरकार को वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने मदद करेगी। 65 शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संपत्ति और कोष प्रबंधकों के बीच ब्लूमबर्ग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 92 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि वे भारत में निवेश बढ़ाने को इच्छुक हैं अगर वहां निवेश को आसान बनाया जाए। यह सर्वेक्षण जुलाई से सितंबर के बीच कराया गया था जिसे दिसंबर में जारी किया गया है। निवेशक भारत के बॉन्ड बाजार में संभावनाएं देख रहे हैं लेकिन पूंजी नियंत्रण, तरलता की कमी और इलेक्ट्रॉनिक पहुंच का अभाव को बड़ी बाधा बताया।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर सीएसआर खर्च

सूचीबद्ध कंपनियों ने सीएसआर पर करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए

सचिन मामबटा
मुंबई, 12 दिसंबर

सीएसआर पर खर्च

साल	रकम (करोड़ रुपये)
2014-15	6,552
2015-16	8,489
2016-17	9,064
2017-18	10,128
2018-19	11,867

स्रोत : एनएसईइन्फोबेस डॉट कॉम

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के जरिए कंपनियां परोपकार पर अपना योगदान लगातार बढ़ा रही हैं। वित्त वर्ष 2019 में इस मद में कंपनियों ने कुल 11,867.2 करोड़ रुपये खर्च किए। वित्त वर्ष 2015 में सीएसआर अनिवार्य किए जाने के बाद का यह सर्वोच्च आंकड़ा है।

कंपनी अधिनियम के मुताबिक, फर्मों को पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो फीसदी सीएसआर की परियोजनाओं पर खर्च करना जरूरी है। यह खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर खेलकूद या फिर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर हो सकता है। वित्त वर्ष 2019 में सीएसआर पर किया गया खर्च एक साल पहले के 10,128.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 17.2 फीसदी ज्यादा है। यह जानकारी कॉरपोरेट ट्रैकर एनएसईइन्फोबेस डॉट कॉम के आंकड़ों से मिली। वित्त वर्ष 2015 में यह 6,552.5 करोड़ रुपये रहा था। सबसे ज्यादा खर्च (4,406 करोड़ रुपये) शिक्षा के प्रोत्साहन (विशेष शिक्षा व रोजगार से जुड़ी स्किल पर खर्च खास तौर से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के अलावा जीविका से जुड़ी परियोजनाएं) पर खर्च शामिल है और यह अनुसूची 7 (2) शामिल है। दूसरा बड़ा खर्च (3,206.5 करोड़ रुपये) अनुसूची 7 (1) के तहत हुआ। इसमें भूखमरी, गरीबी और कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ भारत कोष में योगदान वाली चीजें शामिल है, जिसका गठन भारत सरकार ने साफ-सफाई को बढ़ावा देने और हर नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए किया है। ग्रामीण विकास वाली परियोजनाओं को 1,319 करोड़ रुपये मिले और इस सूची में इसका स्थान तीसरा रहा। पर्यावरण के लिए भी कंपनियों ने रकम आवंटित की। साथ ही सेना के फायदे व आपदा प्रबंधन में भी कंपनियों ने योगदान किया। इस मामले में महाराष्ट्र व गुजरात शीर्ष पर रहे। महाराष्ट्र में 501 कंपनियों ने 931.4 करोड़ रुपये का योगदान किया। यह एनएसई में सूचीबद्ध 1360 फर्मों में से 1015 कंपनियों का आधा है, जिन्हें सीएसआर पर कुछ खर्च करना जरूरी था और जिसके आंकड़े उपलब्ध है। सकल राज्य घरेलू उत्पादों के लिहाज से महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे है और यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से मिली। गुजरात भी पांच अग्रणी राज्यों में शामिल है।

बिहार जैसे राज्य (जो विकास की रैंकिंग में नीचे है) की रैंकिंग सीएसआर के मामले में भी कमजोर है। वित्त वर्ष 2019 में बिहार को 209 कंपनियों से योगदान मिला और इस पर कुल 274.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उत्तर पूर्वी राज्यों को भी इस मामले में कम रकम मिली। अरुणाचल प्रदेश को 170 कंपनियों से 134.2 करोड़ रुपये मिले। सिक्किम और मेघालय जैसे अन्य राज्यों को भी इतनी ही रकम मिली। विशेषज्ञों ने कहा, बताया जाता है कि बड़े खर्च पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि आखिर यह कैसे खर्च हुआ। इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया (आईआईएएस) के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अमित टंडन ने कहा, यह सामान्य बन गया है। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके असर का आकलन कर रही हैं और लोग इसकी जरूरत समझ रहे हैं।

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, सीएसआर पर कम बजट कुछ कंपनियों के लिए निगरानी की व्यवस्था अपनाने में अवरोधक हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ उन फर्मों के लिए बन सकता है, जिसका बजट ज्यादा है। छोटी कंपनियां बाहरी अंकेक्षण के लिए किसी एजेंसी को काम सौंपना महंगा पा सकती हैं।

आगाज पर 50 फीसदी उछल गया उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस का शेयर

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 12 दिसंबर

अच्छी सूचीबद्धता की हालिया प्रवृत्ति को जारी रखते हुए उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक का शेयर गुरुवार को सूचीबद्ध होने के साथ करीब 70 फीसदी उछल गया। पिछले हफ्ते इसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेशकों की भारी मांग देखी गई थी। पहले दिन यह शेयर कारोबार की समाप्ति पर 50 फीसदी की उछाल के साथ 55.3 रुपये पर बंद हुआ जबकि आईपीओ कीमत 37 रुपये प्रति शेयर थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक का शेयर एनएसई पर 62.8 रुपये के उच्चस्तर और 53 रुपये के निचले स्तर को छू लिया था, जहां 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयरों का लेनदेन हुआ। उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक ने आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपये जुटाए हैं और आईपीओ को 170 गुने से ज्यादा आवेदन मिले थे।

विश्लेषकों ने कहा, उचित मूल्यांकन, स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता और कारोबारी बढ़त की ठीक-ठाक रफ्तार ने निवेशकों को आकर्षित किया।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, माइक्रोफाइनैंस संस्थान के तौर पर उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज का अनुभव और ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक को स्मॉल फाइनैंस बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी प्रतिभागियों में शामिल कर देगा।

आईपीओ के जरिए उज्जीवन ने 750 करोड़ रुपये जुटाए हैं और यह पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए है। सूचीबद्धता की प्राथमिक वजह स्मॉल फाइनैंस बैंक पर आरबीआई के दिशानिर्देश का पालन है। उज्जीवन एसएफबी, उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। केंद्रीय बैंक ने सभी स्मॉल फाइनैंस बैंक को एकल आधार पर कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर सूचीबद्ध होना अनिवार्य किया है। आईपीओ के बाद उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज की इस बैंक में हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटकर 84 फीसदी रह गई है।

दिलचस्प रूप से मूल कंपनी उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज का शेयर 3.3 फीसदी टूटकर 329 रुपये पर बंद हुआ। अभी उज्जीवन एसएफबी का बाजार पूंजीकरण 9,661 करोड़ रुपये है। इस बीच, उज्जीवन फाइनैंशियल का बाजार पूंजीकरण महज 3,993 करोड़ रुपये है जबकि स्मॉल फाइनैंस बैंक में उसकी हिस्सेदारी का मूल्यांकन 8,115 करोड़ रुपये है।

शानदार सूचीबद्धता के बाद भी एचएनआई ने गंवाई रकम

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ में उधार लेकर आवेदन करने वाले धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) को नुकसान उठाना पड़ा जबकि इसकी सूचीबद्धता शानदार रही। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा, कर्ज लेकर आवेदन करने वाले तथाकथित गैर-संस्थागत निवेशकों (एचएनआई) के लिए ब्रेक-ईवन कीमत करीब 66 रुपये प्रति शेयर रही। उज्जीवन एसएफबी का शेयर 63 रुपये की ऊंचाई छूने के बाद 55.3 रुपये पर बंद हुआ। एक निवेश बैंकर ने कहा, ऐफल इंडिया, आईआरसीटीसी और आरबीएल बैंक का प्रदर्शन सूचीबद्धता पर शानदार रहा था और इसे देखते हुए ही एचएनआई उज्जीवन एसएफबी को लेकर उत्साहित थे। एचएनआई श्रेणी में 486 गुने से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ रुपये के शेयर आवंटन के लिए एक निवेशक को 486 करोड़ रुपये उधार लेने पड़े होंगे। *समी मोडक*

ऐक्सिस की याचिका पर सैट में सुनवाई पूरी

जश कृपलानी
मुंबई, 12 दिसंबर

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग मामले में ऐक्सिस बैंक की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। इस पर ट्रिब्यूनल 17 दिसंबर को निर्देश जारी करेगा। बैंक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से गिरवी रखे शेयर को जब्त करने के एनएसडीएल के कदम के बाद सैट के हस्तक्षेप की मांग की थी।

ब्रोकरेज ने 100 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट सुविधा के बदले बैंक के पास शेयर गिरवी रखे थे। 11 नवंबर के सेबी के अंतरिम आदेश में कार्वी के खाते से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी, लेकिन अपवाद के तौर पर लाभार्थी मालिक व क्लाइंटों के लिए यह आदेश नहीं था, बशर्ते उन्होंने प्रतिभूतियों से संबंधित पूरा भुगतान कर दिया हो। ऐक्सिस बैंक ने कहा था कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर उसका 80 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि शेयर जब्ती के कारण बैंक उन गिरवी शेयरों को भुनाने में अक्षम है।

सुस्त संपत्ति बाजार में सतर्कता बरत रही एलऐंडटी रियल्टी

कंपनी ने संयुक्त उपक्रम मॉडल में जोखिम को देखते हुए विकास प्रबंधन अनुबंध नहीं करने की रणनीति अपनाई है

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 12 दिसंबर

इंजीनियरिंग एवं निर्माण दिग्गज एलऐंडटी की रियल एस्टेट इकाई एलऐंडटी रियल्टी कई अच्छी आवासीय परियोजनाएं पूरी करने के बावजूद अपना व्यवसाय सतर्कता के साथ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कंपनी ने दो महीने पहले नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके में तैयार किए गए 510 अपार्टमेंट में से 490 की बिक्री की है। एलऐंडटी रियल्टी के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्रीकांत जोशी ने कहा कि मुंबई के मुलुंद इलाके में शुरू की जाने वाली परियोजना में भी ग्राहकों की अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है।

जोशी ने कहा कि कंपनी वित्तीय रूप से दबाव झेल रहे रियल एस्टेट डेवलपरों के साथ भागीदारी को लेकर बेहद सतर्क बनी हुई है, क्योंकि मौजूद समय में भागीदारी जोखिम काफी अधिक है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जेएलएल ने पिछले महीने कहा था कि देश में 66 अरब डॉलर मूल्य की परियोजनाएं रुकी हुई हैं।

उन्होंने कहा, 'हम फिलहाल ऐसी 10-15 परियोजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने की दर 1:25 होगी।'

एलऐंडटी रियल्टी ने वर्ष 2017 में मुलुंद में एक भूखंड विकसित करने के लिए मुंबई स्थित प्रॉपर्टी डेवलपर निर्मल के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया था। हालांकि कंपनी संयुक्त उपक्रमों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह इस मॉडल में जोखिम को देखते हुए फिलहाल विकास प्रबंधन अनुबंध नहीं करेगी।

जेएलएल का कहना है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार नोटबंदी, रेरा और जीएसटी के बाद समेकन के दौर से गुजर रहा है। डेटा विश्लेषण फर्म प्रॉपइक्विटी ने हाल में कहा कि वर्ष 2011-12 में प्रमुख 9 शहरों में परिचालन कर रहे लगभग 50 प्रतिशत रियल एस्टेट डेवलपर इस व्यवसाय से बाहर हो चुके हैं या उन्होंने कमजोर मांग और नियामकीय चुनौतियों की वजह से बड़े बिल्डरों के साथ समझौते कर लिए हैं।

जोशी ने कहा कि जहां अपनी पिछली परियोजनाओं में वह ग्राहकों के बीच पहुंचने के लिए ब्रांड पहचान पर भरोसा करते थे, वहीं अब यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों के लिए ब्रांड पर भरोसा करने से पहले मूल्य, स्थान और डिजाइन भी उपयुक्त हों।

उन्होंने कहा, 'आज का ग्राहक होशियार है और हमें सतर्क रहना होगा।' जोशी ने कहा कि अपार्टमेंटों में आकार भी छोटे हो रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, 'शुरू में अपार्टमेंट में 2-बेडरूम फ्लैट की कीमत 2.25 करोड़ रुपये होती थी। वहीं अब हम 1.5 करोड़ रुपये (मुलुंद में) की कीमत पर इन्हें पेश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि कंपनी मास्टर प्लानिंग में बदलाव ला रही है। जोशी का कहना है, 'मौजूदा समय में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पहले ग्राहक को कब्जा सौंपने तक क्लबहाउस भी तैयार हो जाए।'

मार्जिन पर दबाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह अभी मजबूत एक अंक में है। उन्होंने कहा कि यदि हमें 12-13 प्रतिशत मार्जिन भी मिलता है तो यह अच्छा है।

रियल एस्टेट के अच्छे दिनों के दौरान डेवलपर प्रमुख आवासीय परियोजनाओं में 40-50 प्रतिशत मार्जिन कमाते थे। कंपनी हैदराबाद, बेंगलूरु में कार्यालय परियोजनाएं भी तैयार कर रही है और इस पर आंतरिक रूप से चर्चा कर रही है कि भविष्य में इनकी बिक्री किस तरह से की जाएगी।

गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलीं चार नई परियोजनाएं

बीएस संवाददाता
मुंबई, 12 दिसंबर

गोदरेज प्रॉपर्टीज (जीपीएल) ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) में तीन नई और बेंगलूरु में एक परियोजना हासिल की है जिससे उसकी नई विकास क्षमता में लगभग 1.27 करोड़ वर्ग फुट का इजाफा होगा।

जीपीएल ने नवी मुंबई के तेजी से बढ़ रहे आवासीय बाजार में 100 एकड़ से अधिक की टाउनशिप परियोजना विकसित करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया है। यह परियोजना 75 लाख करोड़ वर्ग फुट के विकास क्षेत्र की पेशकश करेगी और इसे आवासीय परियोजना के तौर पर विकसित किया जाएगा।

दूसरी परियोजना एमएमआर के तेजी से उबर रहे अंबरनाथ बाजार में 6.4 एकड़ के भूखंड के विकास के लिए निसराग निर्माण डेवलपर्स के साथ संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का विकास एरिया 11 लाख वर्ग फुट होगा और इसे समूह आवासीय परियोजना के तौर पर विकसित किया जाएगा।

तीसरी परियोजना तेजी से विकसित हो रहे ठाणे शहर में भूमि की एकमुश्त खरीद से जुड़ी हुई है। 8 एकड़ वाली इस परियोजना से लगभग 0.01 करोड़ वर्ग मीटर (11 लाख वर्ग फुट) का विकास क्षेत्र जुड़ जाएगा जिसमें कुछ रिटेल स्पेस के साथ आवासीय अपार्टमेंट मुख्य रूप से शामिल होंगे।

कंपनी को मिली चौथी परियोजना केआईएडीबी हार्डवेयर पार्क, बगालुर (उत्तरी बेंगलूरु) में यूनिवर्सल बिल्डर्स के प्रवर्तकों के साथ बनाया गया संयुक्त उपक्रम है। यह परियोजना 22 एकड़ के भूखंड पर लगभग 0.028 करोड़ वर्ग मीटर की अत्याधुनिक किफायती आवासीय परियोजना होगी। यह भूखंड मुख्य स्टेट हाईवे 104 पर है और यह हवाई अड्डे तथा बेंगलूरु के कई प्रमुख स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा, 'हम अपने विकास पोर्टफोलियो में इन चार नई परियोजनाओं को शामिल कर बेहद उत्साहित हैं। ये परियोजनाएं देश के प्रमुख रियल एस्टेट बाजार में हमारी उपस्थिति मजबूत बनाने की रणनीति के लिहाज से अनुकूल हैं और इससे जीपीएल को अपनी बाजार भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं को गति मिलेगी। हम इन सभी स्थानों पर आकर्षक परियोजनाएं पेश करने की संभावना तलाश रहे हैं।' मौजूदा समय में कंपनी की परियोजनाओं का निर्माणाधीन आकार 12.5 करोड़ वर्ग फुट है।

पीरामल रियल्टी का ओंकार संग करार

पीरामल रियल्टी ने मुंबई में एक परियोजना के विकास के लिए ओंकार रियल्टर्स के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है। कंपनी अगले कुछ साल में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। पीरामल समूह की रियल एस्टेट इकाई पीरामल रियल्टी ने माहिम में आवासीय परियोजना के लिए ओंकार के साथ दूसरा संयुक्त विकास करार (जेडीए) किया है। कंपनी का इरादा चार एकड़ से अधिक क्षेत्र में 22 लाख वर्ग फुट का विकास करना है। कंपनी अगले कुछ साल में इस परियोजना में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

पीरामल रियल्टी के संस्थापक आनंद पीरामल ने कहा कि यह आवासीय परिसर मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर (बीकेसी) के पास स्थित होगा। यह माहिम-बीकेसी क्षेत्र की सबसे बड़ी आवासीय परियोजना होगी। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में कुल 3,400 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग हासिल की। *एजेंसियां*

लंबा खिंचेगा भूषण पावर का दिवालिया समाधान

ईशिता आयान दत्त और नम्रता आचार्य
कोलकाता/हैदराबाद, 12 दिसंबर

एनसीएलएटी ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी तय की

कानूनी विवाद में फंसा भूषण पावर ऐंड स्टील के समाधान की प्रक्रिया दिवालिया संहिता में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी के बाद भी लंबी खिंच सकती है। कामयाब बोलीदाता जेएसडब्ल्यू स्टील की अपील पर सुनवाई कर रहा नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी तय की है। इसके अतिरिक्त लेनदारों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। लेनदार दो आधार पर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। वे चाहते हैं कि जेएसडब्ल्यू समाधान योजना क्रियान्वित करे और प्रवर्तन निदेशालय भूषण पावर ऐंड स्टील की परिसंपत्तियां जब्त करने के आदेश को वापस ले। सूत्रों ने कहा, इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

लेनदारों ने जेएसडब्ल्यू स्टील को तब पत्र लिखा था जब एनसीएलटी ने सौदा पूरा करने की मंजूरी दी थी। हालांकि कंपनी लेनदेन से जुड़ी जटिलताएं दूर होने का इंतजार कर रही थी।

एक लेनदार ने कहा, जब इन संशोधनों पर अधिसूचना जारी हो जाएगी तब शायद मामला वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक अन्य लेनदार ने कहा, इस पर कुछ भ्रम है कि क्या यह नए मामलों पर लागू होगा या फिर मौजूदा पर भी। भूषण पावर ऐंड स्टील पर लेनदारों का करीब 47,000 करोड़ रुपये बकाया है।

हालांकि खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर कुमार सौरभ सिंह ने स्पष्ट किया कि इसे पिछले संशोधन की तरह ही लागू किया जाएगा, जो मौजूदा व लंबित मामलों के लिए है।

अगर लेनदार सर्वोच्च न्यायालय से मामला वापस लेने का फैसला लेते हैं तो एनसीएलएटी में मामला सुलझ जाएगा। सितंबर में भूषण पावर ऐंड स्टील के लिए एनसीएलटी ने जेएसडब्ल्यू की 19,700 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ ऐसा हुआ था।

एनसीएलटी ने जेएसडब्ल्यू स्टील की योजना मंजूर करते समय आयकर अधिनियम 1961 के तहत सांविधिक प्राधिकरण, कंपनी मामलों के मंत्रालय, पंजीकरण व स्टांप विभाग, आरबीआई आदि की तरफ से मांगी गई राहत का निपटारा कर दिया था।

इससे जेएसडब्ल्यू इस आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी जाने के लिए प्रोत्साहित हुई। अपनी अपील में जेएसडब्ल्यू ने धनशोधन निरोधक कानून से विशिष्ट राहत मांगी थी, खास तौर से भूषण पावर ऐंड स्टील में हुई धोखाधड़ी के संदर्भ में। साथ ही कंपनी ने अन्य प्राधिकरणों की तरफ सो होने वाली कानूनी कवायद से भी राहत मांगी थी।

जेएसडब्ल्यू की अपील के बाद अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। यह मामला अभी एनसीएलएटी में है।

संपत्ति की जब्ती अन्य मामले में भी समाधान आवेदकों के लिए मुश्किल के तौर पर सामने आई। समझा जाता है कि मित्तल ने एस्सार स्टील मामले में पिछली फौजदारी मामलों से छूट मांगी है।

अशोक लीलैंड के नए प्रबंध निदेशक व सीईओ बने सोढी

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 दिसंबर

वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने विपिन सोढी को कंपनी का नया मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नवंबर 2018 में विनोद के दसारी के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था, लेकिन दसारी मार्च 2019 तक कंपनी के साथ बने रहे थे।

सोढी के पास विनिर्माण व इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ तीन दशक से ज्यादा काम करने का अनुभव है। वह नवंबर 2019 में औपचारिक तौर पर हिंदुजा समूह से जुड़े।

अपनी नई भूमिका में वह हिंदुजा समूह के ग्लोबल ऑटोमोटिव पोर्टफोलियो के एकीकरण, बढ़त व भविष्य की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अशोक लीलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा, नेतृत्व के लिहाज से विपिन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वह काफी जुनूनी व्यक्ति हैं। सभी हितधारकों के साथ काम करने की उनकी क्षमता और उसे आगे बढ़ाना अशोक लीलैंड के लिए मूल्यवान होगा। मुझे भरोसा है कि उनके नेतृत्व के तहत कंपनी नए कीर्तिमान बनाएगी।

सोढी ने कहा, मैं सभी हितधारकों व कर्मचारियों के साथ काम करते हुए अशोक लीलैंड के नए विजन को पूरा करने में मदद करूंगा, जिसके तहत कंपनी को दुनिया के 10 विनिर्माताओं में शामिल होना है।

'आर्थिक सुधार न होने पर घटेगी रेटिंग'

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चेताया

- एजेंसी ने भारत की जीडीपी वृद्धि 2019-20 में 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया
- एसऐंडपी ने कुछ दिन पहले ही भारत की रेटिंग एवं आउटलुक को यथावत रखने की घोषणा की थी
- ढांचागत वृद्धि में बड़ी कमजोरी आने पर घटाई जाएगी रेटिंग

एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 2019-20 में 5.1 फीसदी रहने का गुरुवार को अनुमान जताया। एजेंसी ने कहा कि अगर आर्थिक सुधार नहीं हुआ तो देश की रेटिंग घटाई जा सकती है।

एसऐंडपी ने अपने इस बयान से कुछ दिन पहले ही भारत की रेटिंग एवं आउटलुक को बरकरार रखने की घोषणा की थी। इससे एक महीने पहले मूडीज ने भारत की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग में कटौती की थी। इस समय एसऐंडपी की भारत की रेटिंग 'बीबीबी-' और आउलटुक 'स्थिर' है।

एसऐंडपी ने भारत पर 'बहुधा पूछे जाने वाले सवालों' पर एक नोट में कहा कि एजेंसी के चालू वित्त वर्ष में कमजोर आर्थिक वृद्धि के अनुमान के बावजूद भारत की लंबी अवधि में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करने की संभावनाएं यथावत बना हुई हैं। एजेंसी ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि घटकर 5.1 फीसदी रहेगी। इस आकलन में अगले कुछ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार होने का हमारा अनुमान भी शामिल है।' एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के ऋण विश्लेषक एंड्रयू वुड ने कहा, 'अगर यह वृद्धि नहीं होती है और यह साफ हो जाता है कि भारत की ढांचागत वृद्धि में अहम कमजोरी आई है तो हम रेटिंग को घटा सकते हैं।'

एसऐंडपी ने कहा कि भारत के राजकोषीय मापदंड कमजोर बने हुए हैं। इन मापदंडों में भारत का राजकोषीय घाटा और केंद्र सरकार के कर्ज में शुद्ध सालाना बदलाव आदि शामिल हैं। इन कमजोरियों को कई वर्षों से भारत की लंबी अवधि की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग 'बीबीबी' में शामिल किया गया है। भारत की राजकोषीय स्थिति में मजबूती के कम आसार हैं। इसने कहा, 'ऐसा लगता है कि यह साल केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिए मुश्किल भरा रहेगा क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण राजस्व आय कमजोर है और सितंबर में कॉरपोरेट कर में बड़ी कटौती का भी असर पड़ने के आसार हैं।' नोट में आगाह किया गया है, 'हमारा अनुमान है कि कॉरपोरेट कर में कटौती जैसे निजी निवेश को बढ़ाने वाले सरकार के उपायों से ढांचागत कमजोरी दूर करने में मदद मिलेगी। भारत के लंबी अवधि में फिर से सतत ऊंची वृद्धि दर हासिल करना ढांचागत सुधारों पर निर्भर करेगा।'

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि एसऐंडपी ने भारत की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग बीबीबी- पर यथावत और आउटलुक 'स्थिर' रखा है। एसऐंडपी के नोट से एक दिन पहले ही सरकार ने इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'एसऐंडपी ने स्थित आउटलुक के साथ भारत की सॉवरिन रेटिंग 'बीबीबी-' बरकरार रखी है। एसऐंडपी का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन करेगी और अगले दो वर्षों में वृद्धि मजबूत रहेगी।'

तिमाही जीडीपी रहेगी 4.3 फीसदीः नोमुरा

जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा के अनुसार, इस साल दिसंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा का मानना है कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में मामूली सुधार होगा और यह 4.7 प्रतिशत रह सकता है।

दिवालिया विधेयक लोकसभा में पेश

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

सरकार ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में अहम बदलाव लाने वाले संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया। इसमें यह प्रस्ताव है कि किसी रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम-से-कम 100 या दस फीसदी खरीदारों को साथ आना जरूरी होगा।

आईबीसी कानून की धारा सात में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो तमाम बदलावों को पश्चवर्ती प्रभाव से लागू करने की बात करता है। यह कानून लागू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नई शर्तों के मुताबिक दिवालिया अर्जी लगानी होगी। जिन मामलों में इकलौते फ्लैट खरीदार ने ही रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की अर्जी लगाई हुई है, उनमें भी संशोधित प्रावधानों का अनुपालन एक महीने के भीतर करना होगा। यह सीमा उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें ऋणदाताओं के समूह के प्रति वित्तीय ऋण की देनदारी है या प्रतिभूतियों या जमा की शक्ल में है और सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के लिए एक ट्रस्टी या एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के पार्टनर मनोज कुमार कहते हैं, 'आईबीसी में प्रस्तावित संशोधनों का मूल मुद्दा दिवालिया प्रक्रिया की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना और निवेशकों के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाना है।' हालांकि सरकार ने उद्योग संगठनों की मांग के अनुरूप एक कंपनी के लिए कुल सीमा नहीं बढ़ाई है। फिलहाल एक कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक लाख रुपये की सीमा रखी गई है। कर्जग्रस्त कंपनियों के खरीदारों को साफ-सुथरा परिवेश देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि कर्जदार कंपनी की संपत्ति की जब्ती, कुर्की या निरोध जैसी आपराधिक प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

आईबीसी संशोधन विधेयक में इस आशय से नया उपबंध 32ए जोड़ा गया है। यह कहता है कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही ऋणग्रस्त कंपनी के खिलाफ उस समय से कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा जब से समाधान योजना स्वीकृत हो जाएगी।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर अंशुल जैन कहते हैं, 'भले ही यह प्रावधान सफल बोलीकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा लेकिन अकेले आईबीसी कानून से यह मसला नहीं दूर हो सकता है। इसके लिए दूसरे कानूनों में जरूरी बदलाव करने होंगे।'

अगले साल से लागू होंगी नई जीएसटी दरें!

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बढ़ी दरों के लिए कमर कस लेनी चाहिए। जीएसटी परिषद राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी के लिए अगले सप्ताह दरों के ढांचे में बदलाव कर सकती है। केंद्र की तरफ से पेश प्रस्ताव में पांच फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 6 से 8 फीसदी करना और 12 फीसदी के स्लैब को खत्म करना शामिल है। कुछ राज्य ऐसे कदम का विरोध कर सकते हैं क्योंकि इसमें गरीबों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों पर कर बढ़ाने की बात कही गई है। इसके बजाय राज्यों ने 18 फीसदी के स्लैब को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'परिषद के समक्ष कई विकल्प रखे जाएंगे। इनमें से एक पांच फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 6 फीसदी करना है। ऐसा करना आसान होगा। हालांकि इस स्लैब को बढ़ाकर 8 फीसदी से अधिक नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में 12 फीसदी के स्लैब को खत्म कर उसके अंतर्गत आने वाले उत्पादों को 8 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब में शामिल किया जा सकता है।'

परिषद की बैठक 18 दिसंबर को होगी, जिसमें जीएसटी संग्रह को सुधारने के उपायों पर चर्चा होगी। केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि निचले स्लैब में फेरबदल का कड़ा विरोध किया जाएगा। आइजैक ने कहा, 'यह अजीब प्रस्ताव है। मैं गरीबों पर कर का बोझ बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। यह अन्याय होगा।' उन्होंने कहा कि केरल ने कर संग्रह सुधारने के लिए 18 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 22 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। आइजैक ने कहा, 'अगर जरूरत पड़े तो ऊपरी स्लैब में बढ़ोतरी हो। 18 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 22 फीसदी या 25 फीसदी किया जा सकता है।'

पांच फीसदी के स्लैब में मुख्य रूप से आवश्यक जिंस जैसे बुनियादी कपड़े, फुटवियर और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि पांच फीसदी के स्लैब को बढ़ाने से मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा, 'हालांकि मैं अपने पास अंतिम प्रस्ताव आने तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पांच फीसदी के स्लैब की दर को बढ़ाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। 18 फीसदी के स्लैब में बदलाव से मदद मिल सकती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या यह व्यावहारिक है।'

पांच फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर छह फीसदी करने का मतलब है कि अगर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये मानकर चलते हैं तो राजस्व में हर महीने 1,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं इसे बढ़ाकर 8 फीसदी करने से हर महीने 3,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। करीब 60 फीसदी राजस्व की प्राप्ति 18 फीसदी स्लैब के दायरे में आने वाले उत्पादों से होती है। इसके अलावा 13 फीसदी राजस्व 12 फीसदी के स्लैब से, 22 फीसदी राजस्व 28 फीसदी कर के दायरे में आने वाले उत्पादों से और शेष राजस्व 5, 3 और एक फीसदी के स्लैब से प्राप्त होता है। केरल ने प्रस्ताव के मुताबिक अगर 18 फीसदी के स्लैब की दर बढ़ाकर 22 फीसदी की जाती है तो हर महीने 13,000 रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जीएसटी चोरी रोकने के लिए लॉटरी योजना

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

ग्राहकों में विक्रेताओं से बिल लेने की आदत होगी विकसित

विक्रेता से बिल की कॉपी मांगना अब ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ग्राहकों में बिल लेने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने पर विचार कर रही है। इस उपाय पर राजस्व संवर्द्धन अधिकारियों की समिति काम कर रही है, जिसका मकसद जीसटी संग्रह में इजाफा करना है। इस प्रस्ताव को 18 दिसंबर को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की होने जा रही बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है।

इस योजना के तहत उपभोक्ता कल्याण निधि का उपयोग भाग्यशाली विजेताओं को मासिक और वार्षिक आधार पर इनाम देने के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसी निधि में मुनाफाखोरी रोधी प्राप्तियों को जमा कराया जाता है। अभी ड्रॉ की रकम निश्चित नहीं की गई है लेकिन यह सालाना ड्रॉ के लिए कुछ लाख रुपये तक और मासिक ड्रॉ के लिए करीब 50,000 रुपये हो सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इस योजना का मकसद उपभोक्ताओं को बिल की कॉपी मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे विक्रेताओं को जीएसटी का अनुपालन करना होगा और कर चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर बहुत से ब्यूटी पार्लर और छोटे होटल बिल ग्राहकों को बिल नहीं देते हैं जहां काफी मात्रा में कर वंचन हो सकता है। लॉटरी योजना के तहत अच्छी खासी राशि दी जाएगी जिससे लोगों को इसमें भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।' लॉटरी योजना उपभोक्ता लेनदेन वाले जीएसटी व्यापार के लिए होगा। उपभोक्ताओं को एक समर्पित पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा जहां से विजेताओं का चुनाव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना की थी। इसमें कंपनियों को ऐसे मुनाफे की रकम को जमा करने की अनुमति दी गई थी, जिसे उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जा सकता था। उपभोक्ता कल्याण निधि के संग्रह का उपयोग देश में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए किया जाता है। जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी रोधी नियमों के मुताबिक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्तिकर्ताओं को ऐसे किसी आपूर्तियों में की गई किसी भी कटौती का आनुपातिक लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में आनुपातिक कम कर देनी चाहिए।

हाल ही में एनएए ने नेस्ले को अंतिम उपभोक्ता तक कर कटौती का लाभ नहीं पहुंचाने पर 90 करोड़ रुपये उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराने का आदेश दिया है। जीएसटी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगाय। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'अधिक संख्या में एजेंसियों को शामिल करने से विजेताओं के चयन में किसी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश को कम होगी।'

अयोध्या में बसेगी आध्यात्मिक नगरी

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 12 दिसंबर

- 3,000 करोड़ रुपये की लागत से इक्ष्वाकुपुरी बसाई जाएगी
- देश-विदेश के पर्यटकों को लुभाने की है योजना

उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी के तौर पर विकसित की जा रही अयोध्या में नए साल में इक्ष्वाकुपुरी समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। अगले सप्ताह विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट में अयोध्या के लिए योगी सरकार कई सौगातें लेकर आ सकती है।

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए अंकोरवाट की तर्ज पर नई आध्यात्मिक नगरी बसाने की योजना है। करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से इक्ष्वाकुपरी के नाम से बसाए जाने वाले इस क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा। अयोध्या में इक्ष्वाकुपुरी सहित कई अन्य बड़ी परियोजनाओं के साथ ही समूचे क्षेत्र के विकास के लिए एक नई शासकीय संस्था बनाई जा रही है। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के नाम से प्रस्तावित इस संस्था के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। हाल ही में मथुरा-वृंदावन के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने ब्रज क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया था।

प्रदेश सरकार का मानना है कि अध्यत्म और पर्यटन के अनूठे आकर्षण वाली इक्ष्वाकुपुरी से अयोध्या में न केवल व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मोटे अनुमान के मुताबिक इक्ष्वाकुपुरी के बन जाने के बाद अयोध्या को 500 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना के तहत आधारभूत ढांचे व सुविधाओं का विकास प्रदेश सरकार करेगी जबकि बाकी का निर्माण अन्य निजी एजेंसी करेगी।प्रदेश सरकार के मुताबिक फिलहाल अयोध्या में हर साल 1.5 से दो करोड़ पर्यटक आते हैं। अधिकांश पर्यटक अयोध्या में कुछ देर बिताकर हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि का दर्शन कर वापस चले जाते हैं। इक्ष्वाकुपुरी के बन जाने के बाद भारतीय अध्यत्म, दर्शन व धर्मशास्त्र की जानकारी के इच्छुक पर्यटक यहां कुछ दिन बिता सकेंगे। इसका विकास अयोध्या में 1,900 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें महज 10 फीसदी ही कंक्रीट का निर्माण होगा, बाकी क्षेत्र में हरियाली होगी। अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग से गुप्तारघाट को 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी जो इक्ष्वाकुपुरी को जोड़ेगी। इसमें एक तरफ सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाए जहां आध्यात्मिक नगरी बनाई जाएगी। इक्ष्वाकुपुरी को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों के नाम से अलग-अलग संकुल होंगे।

इक्ष्वाकुपुरी के अगले भाग को सुविधा परिसर का नाम दिया गया है। इस हिस्से में होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। सुविधा परिसर में भारत के विभिन्न राज्यों को अपने भवन बनाने के लिए जमीन दी जाएगी जहां वे न केवल गेस्ट हाउस बना सकेंगे बल्कि अपने राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों की रेप्लिका बना सकेंगे।

कारोबारियों की जीएसटी शिकायतें दूर करेगा तंत्र

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

दिल्ली उच्च न्यायालय के सख्त रूख के बाद केंद्र सरकार ने कारोबारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे चर्चा और मंजूरी के लिए जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में रखा जा सकता है।

जीएसटी परिषद के संयुक्त सचिव धीरज रस्तोगी के नाम जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन बनाम अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए जोन और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित की जानी है। इस संबंध में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र गठित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस तंत्र में केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटी के अधिकारियों के साथ जीएसटीएन के प्रतिनिधि, कारोबार व उद्योग प्रतिनिधि और जीएसटी हितधारक (जीएसटी प्रेक्टीशनर आदि) शामिल होंगे। इस तंत्र के संबंध में जीएसटी नीति प्रकोष्ठ को 18 दिसंबर को होने वाली आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा करने और इसकी अनुमति के लिए विस्तृत एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत के आदेश के अनुपालन के तहत राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों सूची पहले ही जीएसटीएन की बेवसाइट डाल दी गई है। साथ ही जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा सभी राज्यों को उनकी बेवसाइट का लिंक जीएसटीएन पर मुहैया कराने को कहा गया है। जिससे कि एक ही स्थान पर सभी राज्यों के आईटी शिकायत निवारण समिति के अधिकारियों तक पहुंच बनाई जा सके। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि जीएसटी समस्याएं सुलझाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते महीनों में कई आदेश दिए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो रहा था। पिछले महीने के आखिर में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रूख अपनाया, जिसके बाद अब जीएसटीएन ने शिकायत निवारण तंत्र बनाने की योजना बनाई है।

ममता का केंद्र सरकार पर हमला

अभिषेक रक्षित
दीघा, 12 दिसंबर

ममता ने कहा-

- राज्य में उद्योगपति एजेंसियों के दखल से पूरी तरह महफूज
- देश में निवेशकों के डरे होने की बात कहकर कारोबारी सहूलियत के केंद्र के दावे पर उठाए सवाल
- भारत समेत दुनियाभर में मंदी, मगर पश्चिम बंगाल इससे सुरक्षित

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा कारोबारी माहौल को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला किया। उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य में उद्योगपति एजेंसियों के दखल से महफूज हैं और वे बेफिक्र होकर अपना कारोबार कर सकते हैं।

उन्होंने इस मुद्दे का इस्तेमाल दीघा में आयोजित अपने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बंगाल बिज़नेस कॉन्क्लेव को प्रोत्साहित करने में किया। इस कार्यक्रम का मकसद राज्य में कारोबार लाना है। ममता ने कहा, 'हर कोई डरा हुआ है। आप कैसे अपना कारोबार चलाएंगे। आपको आयकर, सीमा शुल्क, सीबीआई कर जैसे बहुत से कर चुकाने पड़ते हैं। मेरा मानना है कि बंगाल में कोई नहीं कहेगा कि उन्हें कोई समस्या है। समस्या तब पैदा होगी, जब रोजाना कोई आपका दरवाजा खटखटाता है और आपको जगह छोड़ने के लिए कहता है।' हालांकि उन्होंने तुरंत खुद अपने बयान को यह कहते हुए ठीक किया, 'क्षमा चाहती हूं, सीबीआई एक एजेंसी है।' उनका बयान एक तरह से कारोबारी सहूलियत के केंद्र के दावे पर हमला है। केंद्र का दावा है कि कारोबारी सहूलियत में भारत की रैंकिंग सुधर रही है। लेकिन बनर्जी यह कहते हुए इस दावे को खारिज कर रही हैं कि निवेशक डरे हुए हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में केंद्र पर आरोप लगाया था कि उसकी वजह से उद्योगपति कथित रूप से डरे हुए हैं। दरअसल बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज ने एक कार्यक्रम में कुछ नीतियों और मौजूदा कारोबारी माहौल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान आकृष्ट किया था, जिसे लेकर देश में बड़ी बहस चली थी। ममता ने मौजूदा मंदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'विश्व और भारत में भारी संकट है, लेकिन बंगाल क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हमने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। पश्चिम बंगाल में तीन करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और बेरोजगारी की दर में 40 फीसदी कमी आई है।'

उन्होंने कहा कि राज्य रोजगार सृजन और निवेश लाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने इस कॉन्क्लेव में एमएसएमई के केंद्रों की भी घोषणा की। एक परिधान केंद्र कोलकाता के नजदीक नुंगी में स्थापित किया जा रहा है। वहीं स्टील फैब्रिकेशन सेंटर पश्चिमी मिदनापुर में स्थापित किया जा रहा है। लाख केंद्र पुरलिया में और बेल एवं ब्रास मेटल का साझा सुविधा केंद्र बांकुरा में बनाया जा रहा है।

बीएस सूडोकू 3611 | परिणाम संख्या 3610

2			9	8				
8	5		2			4		
	6		3	4	7			
	3		8			9		6
7		5			2		3	
			7	3	8		4	
		8			6		7	5
				2	9			8

5	2	4	7	6	9	8	3	1
7	3	1	5	8	2	4	9	6
6	8	9	1	3	4	5	2	7
2	5	7	9	1	3	6	8	4
4	1	3	8	7	6	2	5	9
8	9	6	2	4	5	1	7	3
9	7	8	6	5	1	3	4	2
1	4	5	3	2	7	9	6	8
3	6	2	4	9	8	7	1	5

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसन
★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2090/2100, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1438, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1518, फ्लैक 1450, डीएमओ 1036, टरपीन लैस बोल्ड 1542

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1060/1200, खुरपा 1000/1080,चाकू 1050/1230, रसकट 850/880, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3325, सिहोरा 3165, बुंदकी 3190, बुढ़ाना 3270,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 925/975, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4350, खल: सरसों 2200/2300, बिनौला 2400/2500, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3780/3800, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4600/4610,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3650/3725, जौ 2050/2070,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7200/7300, बाजरा (गुजरात) 1900/1910, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4100/4200, काबली चना 4700/5900, मूंग 6000/6100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2000, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1250,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3950/3980, हरियाणा 3930/3950, राजस्थान 3850/3950, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2190/2200, गेहूं चोकर (28 किलो) 595

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4325/4375 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2320/2330, बिहार 2375/2380, दाल उड़द छिलका 8800/10700, चना देशी 5000/5075, दाल चना 5100/5300, काबली चना 4900/5800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2800/2850, पूसा 1509 धान 2500/2575, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5150/5200, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, सरसों 4150/4200, गेहूं 2140/2150, नरमा कपास 500/5100

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4100/4150, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 8850/8900, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 255

सतर्क करती चेतावनी

एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपने ताजा नोट में चेतावनी दी है कि लगातार धीमी आर्थिक वृद्धि भारत की सॉवरिन रेटिंग पर असर डाल सकती है। गुरुवार देर शाम जारी एक वक्तव्य में एसऐंडपी ने कहा कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं नजर आता है तो वह भारत की सॉवरिन रेटिंग घटा सकती है। गत माह एक और वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से घटाकर ऋणात्मक कर दिया था। इसके लिए आर्थिक मंदी, आवासीय क्षेत्र में वित्तीय तनाव और वित्तीय क्षेत्र में नकदी की कमी को वजह बताया गया था।

भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और आर्थिक प्रबंधन के जटिल होने से रेटिंग में गिरावट की आशंकाओं में इजाफा ही होगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर छह वर्ष के निचले स्तर तक गिरकर 4.5 फीसदी रह गई। उच्च तीव्रता वाले संकेतक भी आने वाली तिमाहियों में किसी सुधार की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। वृद्धि में भारी गिरावट के लिए अस्थायी और ढांचागत दोनों तरह के कारण उत्तरदायी हैं। हालांकि एसऐंडपी को आर्थिक वृद्धि दर में सुधार की अपेक्षा है लेकिन उसका यह कहना भी सही है कि सतत उच्च वृद्धि की वापसी काफी हद तक ढांचागत सुधारों पर निर्भर करेगी। अन्य कारकों के अलावा बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में तनाव भी अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को बाधित कर रहा है। इसका असर धीमी वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों के पारेषण को भी प्रभावित किया है। जबकि व्यवस्था में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।

इसके अलावा एसऐंडपी का यह कहना एकदम उचित है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के जटिल क्रियान्वयन ने भी अर्थव्यवस्था में कुछ विसंगतियां पैदा की हैं। जीएसटी तंत्र की दिक्कतों को दूर करने पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। जीएसटी परिषद को व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

जीएसटी के कमजोर प्रदर्शन ने केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया है। दरअसल देश की राजकोषीय स्थिति एक और खतरे का संकेत है। एसऐंडपी का मानना है कि देश का सरकारी घाटा इस वर्ष में बढ़कर जीडीपी के 7.4 फीसदी तक हो जाएगा। वृहद आर्थिक परिदृश्य सुधरने पर अगले वित्त वर्ष में संयुक्त घाटे के 7.1 फीसदी रह जाने की आशा है। बहरहाल, राजकोषीय घाटे और संचयी ऋण में वृद्धि भी सॉवरिन रेटिंग पर दबाव डाल सकती है। ऐसे में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अहम राजकोषीय विस्तार का विकल्प अब व्यवहार्य नहीं रह गया है।

सरकार को वृद्धि दर बहाल करने के तरीके तलाश करने होंगे। इसके साथ ही उसे राजकोषीय संतुलन कायम करने को लेकर भी प्रतिबद्ध रहना होगा। सॉवरिन रेटिंग पर पड़ रहे दबाव के अलावा उच्च घाटा और उधारी भी वित्तीय तंत्र में विसंगति उत्पन्न कर सकती है। इसका असर मध्यम अवधि में वृद्धि पर पड़ेगा। ऐसे में पूरा ध्यान बाजार की गतिविधियों पर प्रतिबंध कम करने पर होना चाहिए। इसमें कारक बाजार मसलन श्रम और भूमि बाजार भी शामिल हैं। ऐसा करके ही वृद्धि को गति दी जा सकती है। सरकार को वैश्विक व्यापार को लेकर अपने रुख पर भी नये सिरे से विचार करना चाहिए। बीते कई वर्षों से निर्यात में ठहराव है। यह भी उच्च वृद्धि दर की वापसी को बाधित करने वाला है। आर्थिक वृद्धि में तेज गिरावट स्पष्ट बताती है कि देश को कई स्तरों पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नीति निर्माता अगर वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के विचार की अनदेखी न करें तो बेहतर होगा।

अजय मोहंती

अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार का रुख

ढांचागत सुधारों का संबंध निजीकरण, भूमि और श्रम से उतना नहीं है जितना कि यह निजी उपक्रमों के दायरे में विस्तार और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादक बनाने से है। बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरकर 4.5 फीसदी रह गई। पूरे वर्ष के लिए यह अधिक से अधिक 5 फीसदी रहेगी। आम आदमी को यह समझ नहीं आ रहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से देश पर विकास पुरुष का शासन होने के बावजूद वृद्धि दर 7.5 फीसदी से गिरकर 4.5 फीसदी कैसे रह गई। मायूसी की स्थिति है लेकिन इस अप्रत्याशित स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक आर्थिक दलील सुनने को नहीं मिली जो हालात को स्पष्ट कर सके। अब जरूर सरकार की ओर से आर्थिक दलील सुनने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने पत्रिका 'ओपन' में एक आलेख लिखकर मंदी के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। उनकी मुख्य दलीलें इस प्रकार हैं।

1. हम अभी भी वृद्धि हासिल कर रहे हैं, प्रसन्न रहिए: भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मेरा (उनका नहीं) मानना है कि लोग बिना मंदी को महसूस किए मंदी की बात करते हैं। परिभाषा की बात करें तो लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी में कमी आने पर ऐसा कहा जा सकता है। यह सच है लेकिन देवराय अनुमान बनाम हकीकत की बात पर चूक जाते हैं। लोगों ने मतदान बेहतरी के लिए दिया था या बदतरी के लिए? सन 2014 में क्या वाकई उन्होंने उम्मीद की होगी कि मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के बाद 5 फीसदी की वृद्धि दर मिलेगी।

2. मुद्रास्फीति कम है, प्रसन्न रहिए: चूंकि जीडीपी के आंकड़ों का मुद्रास्फीति के साथ समायोजन किया जाता है इसलिए यदि मुद्रास्फीति 3 फीसदी है तो वर्ष की नॉमिनल वृद्धि 8 फीसदी होगी। वर्ष 2014 के बाद से सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो मुद्रास्फीति में कमी इनमें प्रमुख है। लेकिन इसकी अधिक सराहना नहीं होती। वह कहते हैं कि मुद्रास्फीति गरीबों को अधिक प्रभावित करती है। वह याद दिलाते हैं कि यदि वास्तविक वृद्धि दर 5 फीसदी, मुद्रास्फीति 10 फीसदी और सांकेतिक वृद्धि दर 15 फीसदी होती तो हालत ज्यादा खराब होती।

यहां कई बातें हैं। कम मुद्रास्फीति कम समेकित मांग के कारण है। यह स्वतंत्र चर नहीं है क्योंकि मोदी सरकार के विभिन्न कदम वृद्धि और मुद्रास्फीति में इस गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं। यह एक अनचाहा परिणाम है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुद्रास्फीति को कम करके गरीबों को राहत देना सरकार का नीतिगत लक्ष्य था। हकीकत में मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा किसानों की आय दोगुनी करने का था। चूंकि देश कोई बड़ा कृषि निर्यातक नहीं है इसलिए इससे भारी खाद्य मुद्रास्फीति उभरती।

3. कमजोर वैश्विक कारोबार का दोष है सरकार का नहीं: देवराय कहते हैं कि जीडीपी वृद्धि का कम से कम 3 फीसदी निर्यात से आता है। यदि निर्यात वृद्धि समाप्त हो जाएगी तो जीडीपी वृद्धि दर 6 फीसदी पर सिमट जाएगी। देवराय के मुताबिक निर्यात को तीन कारक प्रभावित करते हैं: वैश्विक मांग, वैश्विक आपूर्ति और विनिमय दर। इनमें से पहले के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती और तीसरे में भी उसका मामूली दखल है। जहां तक आपूर्ति की बात है तो सरकार ने लॉजिस्टिक्स में सुधार के उपाय अपनाए हैं। यानी कुल मिलाकर विशुद्ध निर्यात सीमित बना रहेगा।

यदि यह सब जमीनी घटनाक्रम की तुलना में बहुत असंबद्ध और अकादमिक प्रतीत हो रहा है तो वाकई ऐसा है। सन 2010 में विश्व के वस्त्र निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 36.6 फीसदी थी जो 2018 में घटकर 31.8 फीसदी रह गई क्योंकि श्रम की लागत बढ़ी और तमाम ढांचागत बदलाव देखने को मिले। इसका लाभ वियतनाम और बांग्लादेश को मिला जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 2.9 फीसदी से बढ़कर 6.2 फीसदी और 4.2 फीसदी से बढ़कर 6.4 फीसदी हो गई। जबकि भारत की हिस्सेदारी 3.3 फीसदी से गिरकर 3.2 फीसदी रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में कारोबार करने की छोटी मोटी लागत बहुत अधिक है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों उत्तरदायी हैं। इसे ढांचागत सुधारों की मदद से हल किया जा सकता है लेकिन देवराय के अनुसार यह दलील बेतुकी है। अगले बिंदु पर गौर कीजिए।

4. ढांचागत बनाम चक्रीय की बहस बेमानी है: देवराय लिखते हैं कि संकट की प्रकृति के ढांचागत या चक्रीय होने को लेकर एक बहस चल रही है जो बेमानी है। यह बेमानी क्यों है? क्योंकि उनके मुताबिक सरकार असहाय है। वह मानते हैं कि ढांचागत बदलाव का अर्थ केवल निजीकरण और श्रम एवं भूमि कानूनों में बदलाव है। वह कहते हैं कि निजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हड़बड़ी नहीं की जा सकती। विधायी बदलाव आवश्यक हैं जो संसद ही कर सकती है। जबकि सर्वाधिक मूल्यवान परिसंपत्ति यानी भूमि पर प्रायः राज्य सरकारों का आधिपत्य है। इसे केंद्र सरकार नहीं बेच सकती।

देवराय कहते हैं कि भूमि और श्रम आंशिक रूप से राज्य का मसला हैं और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ने भूमि की लागत बढ़ाई और बुनियादी परियोजनाओं को पूरा करना कठिन कर दिया। उनके मुताबिक देश की वृद्धि दर में राज्यों के क्रियाकलाप का भी पूरा असर होता है और अकेले केंद्र सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। सच तो यह है कि ढांचागत सुधारों का निजीकरण, भूमि या श्रम से ज्यादा लेनादेना नहीं होता। इसका संबंध निजी उद्यमों के दायरे के विस्तार तथा उनको प्रतिस्पर्धी और उत्पादक बनाने की इजाजत से अधिक है। इसकी शुरुआत कारोबार करने की छिटपुट लागत खत्म करने और राज्यों में भ्रष्टाचार के समापन से होनी चाहिए। वर्ष 2015 में एक आलेख में मैंने पूछा था कि आखिर भाजपा के इकलौते वोट जुटाऊ नेता (जो राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए वोट जुटाते हैं) प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के शासन वाले राज्यो के साथ तालमेल करके हमें क्यों नहीं दिखाते कि राज्य स्तर पर किन सुधारों को अंजाम दिया जा सकता है?

कुल मिलाकर देवराय के मुताबिक 5 फीसदी की वृद्धि दर में दिक्कत की कोई बात नहीं। यह 6 फीसदी तक हो सकती है और अभी जो 'साफ-सफाई' चल रही है वह अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक और किफायती बनाएगी। परंतु ऐसा रातोरात नहीं होगा। देवराय की बातें इस बारे में बहुत उपयोगी हैं कि आप इस सरकार से मंदी को लेकर क्या कदम उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? आखिर हम सभी यह बात जानना चाहते हैं। इसका सीधा उत्तर है: कुछ खास नहीं।

तीन ऐसे खतरनाक मिथक जिनसे बना रहा आशावाद

नीति नियम

मिहिर शर्मा

मंदी के इस दौर में मौजूदा सरकार जो कदम उठा रही है उन्हें देखकर लगता है कि वह वाकई अपने ही प्रोपगंडा पर यकीन करती है। कुछ लोगों की आशंका है कि असहज करने वाले आंकड़े छिपाने और निवेशकों तथा मतदाताओं के समक्ष गुलाबी तस्वीर पेश करने की उसकी प्रवृत्ति बताती है कि सरकार निजी तौर पर सोचती कुछ है और सार्वजनिक रूप से बताती कुछ और है। परंतु यह गलत हुआ तो? यदि सरकार वाकई अपनी इन बातों पर यकीन करती हो तो? इससे सरकार की आकलन और विश्लेषण क्षमताओं पर कुछ सवाल उठते हैं लेकिन यह उसे छल के आरोप से बरी करता है।

सन 2014 से ऐसे आशावादी लोगों की कमी नहीं रही जो अर्थव्यवस्था को लेकर कम नकारात्मक सोच रखने की मांग करते रहे हैं। अब जबकि फिलहाल के लिए ऐसी अधिकांश आवाजें खामोश हो चुकी हैं तो उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि किसी को ऐसे भ्रमित कैसे किया जा सकता है। दरअसल तीन मिथक हैं जिन्होंने हमें इस स्थिति तक पहुंचाया।

पहला मिथक: यह धारणा कि वर्ष 2012-13 का संकट समाप्त हो चुका है। नीतिगत पंगुता के उस दौर को याद कीजिए। उस वक्त ज्यादातर लोग मानते थे कि संप्रग सरकार पंगु थी और उसकी नीति निर्माण क्षमता और राजनीतिक पूंजी की कमी ने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया, निवेश में धीमापन आया और वृद्धि में गिरावट आई। ऐसे में जब 2014 में बहुमत की सरकार आई तो लगा कि संकट हल हो जाएगा। परंतु यह सोचना गलत था। सन 2012-13 का संकट किसी एक सरकार की नीतिगत पंगुता का संकट नहीं था। यह सरकारी मशीनरी की नाकामी का संकट था। नियमन इतने मजबूत नहीं थे कि वृद्धि और पारदर्शिता दोनों हासिल हो सकें, विवाद निस्तारण व्यवस्था कमजोर थी जिससे पूंजी दांव पर लग गई थी। निजी क्षेत्र के प्रतिफल को प्रभावित करने वाले सरकारी कदमों के कारण अतिरिक्त सतर्कता की स्थिति बन गई थी। इस दिशा में ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता जैसे कुछ कदम उठाए गए। परंतु संकट की बुनियादी वजहों का निराकरण नहीं किया जा सका। हम उसी संकट का परिणाम झेल रहे हैं।

दूसरा मिथक: यह धारणा कि भारी-भरकम सरकारी निवेश वृद्धि के लिए पर्याप्त है। यह विचार भी तमाम गलत धारणाओं से उपजा इनमें से एक थी चीन के मॉडल को गलत ढंग से समझना। सच यह है कि बेहतर बुनियादी ढांचा तभी मायने रखता है जब निजी क्षेत्र को उसका उपयोग फायदेमंद लगे। ऐसी बुनियादी परियोजनाओं की सार्वजनिक फंडिंग तभी काम आती है जब निजी क्षेत्र नई परियोजनाओं में निवेश कर अतिरिक्त बुनियादी ढांचे तैयार करता है। चीन की अर्थव्यवस्था राज्य संचालित है। वहां निजी निवेश को आसानी से ऐसा करने को कहा जा सकता है। भारत में इसकी संभावना कम है। खासकर तब जब निजी क्षेत्र के पास फंड की कमी हो। निजी क्षेत्र की दिक्कतों मसलन अतिरिक्त क्षमता, कर्ज के बोझ, कर आंतक और कड़े नियमन को दूर किए बिना बुनियादी क्षेत्र में निवेश की अपेक्षा बेमानी है। ऐसे में राज्य का निवेश अपेक्षित नहीं था। यदि कोई ट्रक खरीदना नहीं चाहता या परिवहन के लिए वस्तुएं ही नहीं हैं तो राजमार्ग निर्माण का कोई मतलब नहीं है।

तीसरा मिथक: अतृप्त भारतीय घरेलू मांग का विचार। हमने कई ऐसे वर्ष देखे हैं जब मांग वृद्धि का सहयोग करती दिखी। परंतु यह एक लोकलुभावन नीति का उत्पाद थी जिसने अस्थायी रूप से आय वृद्धि, घरेलू ऋण विस्तार का सहयोग किया। वहीं खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में ढांचागत कमी ने आपूर्ति क्षेत्र पर सकारात्मक असर डाला। इनमें से कोई कारक स्थायी नहीं है। ऐसे में अनकही अपेक्षा यह थी कि मांग में तब तक तेजी बनी रहेगी जब तक कि निजी क्षेत्र में क्षमता का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित नहीं हो जाता और निवेश को नए सिरे से गति नहीं मिल जाती। परंतु ऐसा लगता है कि यदि ऐसा संभव था तब भी मांग उस सीमा तक नहीं पहुंच सकी। निजी क्षेत्र ऋण की कमी से जूझ रहा है लेकिन उसे उन निवेश परियोजनाओं की धन के लिए पैसे की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है जो अचानक आकर्षक प्रतीत होने लगी हैं। दिक्कत यह है कि देश की उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था के आकार और उसके घटक को लेकर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया जा रहा था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास की हमारे जैसी अवस्था में हो वह निवेश और वृद्धि के लिए केवल घरेलू मांग पर निर्भर नहीं रह सकती। चीन ने वृद्धि का जो चमत्कार किया है या उससे पहले पूर्वी एशिया के देशों में जो हुआ उसकी वास्तविक व्याख्या यह है कि घरेलू आपूर्ति प्रतिक्रिया घरेलू के बजाय वैश्विक मांग से संबद्ध रही। दूसरे शब्दों में भारत को कारोबारी देश बनना होगा। शायद सरकार का यह सोचना सही है कि घरेलू उद्योग को व्यापारिक प्रभावों से बचाया जाए लेकिन यदि ऐसा है तो पहले दिन से सरकार का प्रयास यह होना चाहिए था कि भारतीय विकास को विश्व बाजार तक पहुंच बनानी चाहिए, बस चुनिंदा घरेलू उद्योगों को अस्थायी संरक्षण देना चाहिए। खेद की बात है कि सरकार की दृष्टि केवल घरेलू मांग और उद्योग पर केंद्रित है। विश्व बाजार उसकी नजर से ओझल है। यानी सतत मांग की कमी के कारण निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की समस्या बनी रहेगी।

परंतु यदि मध्यम अवधि में ऐसा आशावादी रुख रखना है तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या नकारात्मकता के इन स्त्रोतों को समाप्त किया जा सकता है? प्रशासनिक और कारक बाजार के ढांचागत सुधार की मदद से ही 2012-13 के संकट से उबरा जा सकता है। निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ सरकारी व्यय की गुणवत्ता सुधारनी होगी, ऐसा करके ही सरकार के पूंजीगत व्यय की मदद से उत्पादकता और वृद्धि में सुधार किया जा सकता है और अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल और निवेश परियोजनाओं की कमी दूर की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नकारात्मकता के बरकरार रहने की पर्याप्त वजह है।

कानाफूसी

महिला सुरक्षा की कवायद

देश भर में महिला सुरक्षा का मुद्दा इस समय चर्चा में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐंटी-रोमियो स्क्वाड को नये सिरे से प्रभावी बनाया है। इस स्क्वाड का गठन मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश में सरकार बनाने के तत्काल बाद किया गया था। इस स्क्वाड की आलोचना भी हुई कि यह सार्वजनिक स्थलों पर बैठे युगलों को परेशान करता है। धीरे-धीरे स्क्वाड का काम शिथिल पड़ गया। अब जबकि हाल के दिनों में महिला सुरक्षा का मुद्दा नये सिरे से जोर पकड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ऐंटी-रोमियो स्क्वाड तथा यातायात विभाग के पुलिसकर्मियों के लिए 25,000 ऐसे कैमरे खरीद रहा है जो शरीर पर लगाए जा सकेंगे। जिलों की पुलिस टीमों को भी महिला सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को लेकर संवेदनशील बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं इन मामलों में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को सत्ताधारी भाजपा के पदाधिकारी ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं ताकि विपक्षी दलों के सवालों के जवाब दिए जा सकें।

अजय मोहंती

आपका पक्ष

धर्मनिरपेक्षता पर सवाल करता विधेयक

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक लाना जितना आसान था उससे कहीं अधिक इसे पारित कराना और लागू करना है। सत्तारूढ़ भाजपा अपार बहुमत से सदन में है पर यह विधेयक कहीं न कहीं हमारे धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल ढांचे पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अगर विवेक से सोचा जाए तो कहीं न कहीं यह देश के दो धर्म के समुदाय के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करेगी। इसे लागू कराना कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र निर्माताओं की सोच, उद्देश्य और उनकी कल्पना के भारतवर्ष का गला घोंटने जैसा होगा। हम 1947 में काफी संघर्ष और बलिदानों के बाद एक स्वतंत्र देश बने और तुरंत हमारा विभाजन भी हो गया। हम धर्म की तलवार से दो भागों में बंट गए। अलग देश पाकिस्तान मांगने वाले जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ले लिया और शेष भारत बचा रह गया। लेकिन हमारे राष्ट्र निर्माता चाहे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू हों, किसी ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा। बल्कि यहां पर हर धर्म के लोगों को रहने, अपना गुजर-बसर करने और धर्म का प्रचार-प्रसार करने की आजादी दी। ये बातें संविधान के मौलिक अधिकारों में भी निहित है। एक सवाल उठता है कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसरा देकर भारत के नागरिक बना सकते हैं तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों, श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोगों को क्यों नहीं? उनके साथ भी तो वहां भेदभाव होता है।

धीरज कुमार, दरभंगा

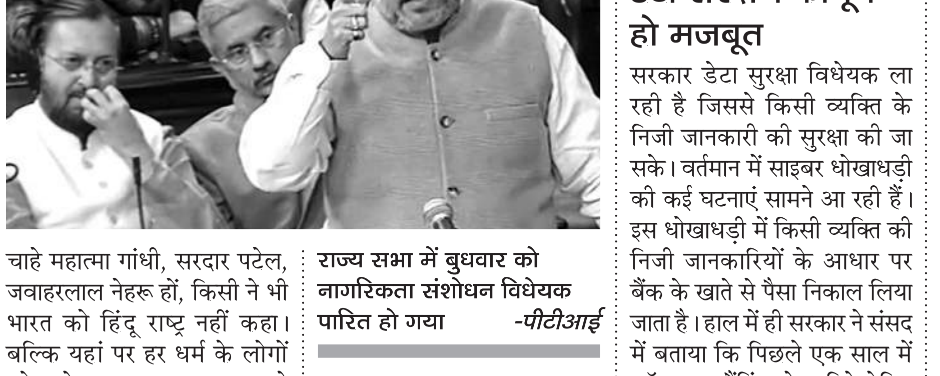

राज्य सभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया *-पीटीआई*

डेटा संरक्षण कानून हो मजबूत

सरकार डेटा सुरक्षा विधेयक ला रही है जिससे किसी व्यक्ति के निजी जानकारी की सुरक्षा की जा सके। वर्तमान में साइबर धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इस धोखाधड़ी में किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों के आधार पर बैंक के खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। हाल में ही सरकार ने संसद में बताया कि पिछले एक साल में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये डेबिट और क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के धोखाधड़ी के मामले 34 हजार से बढ़कर 54 हजार हो गए हैं। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है लेकिन लोग ठग के झांसे में आ ही जाते हैं। अगर सरकार डेटा सुरक्षा कानून बनाती है तो शायद इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामले में कमी आ सकती है। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी आज इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी अर्थात नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक आदि होती है। इसके अलावा व्यक्ति डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर करता है। आज छोटे से छोटे भुगतान के लिए ऑनलाइन या कार्ड से किया जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति की बैंक खाते की जानकारी कोई चुरा सकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की जानकारी चुराने के बाद उनके खाते से राशि निकाल ली जाती है। इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता के साथ सरकार को विशेष साइबर कानून बनाने की जरूरत है जिससे भुगतान करने पर कोई जानकारी लीक न हो। अतः सरकार को इन पहलुओं पर विचार कर डेटा संरक्षण कानून को मजबूत बनाना चाहिए।

आरती कुमारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

रसायन पर लग सकता है डंपिंग रोधी शुल्क

भाषा
नई दिल्ली, 12 दिसंबर

सरकार पांच देशों से आयातित रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकती है। इस रसायन का इस्तेमाल पॉलिएस्टर फाइबर और फिल्म में होता है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस रसायन की डंपिंग की जांच शुरू की है। मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर से मोनो एथीलीन ग्लाइकोल के आयात की जांच शुरू की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से जांच शुरू करने के लिए डीजीटीआर के समक्ष आवेदन किया था।

डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने इसके आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने भी इस आवेदन का समर्थन किया है। एक बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण को प्रथम दृष्टया इन देशों से इस रसायन की डंपिंग के पर्याप्त प्रमाण मिले है। अगर जांच में डंपिंग की पुष्टि हो जाती है तो निदेशालय डंपिंग रोधी शुल्क के बारे में सिफारिश करेगा। जांच जनवरी-सितंबर, 2019 के बीच की गई। निदेशालय 2016-19 के आंकड़ों पर भी गौर करेगा।

सोना लुढ़का, गहनों की मांग बढ़ी

कीमती धातु की कीमतें 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंची

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 12 दिसंबर

इस महीने 18 तारीख को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संभावित इजाफे से पहले सोने के दाम तकरीबन दो महीने के निचले स्तर पर आने के कारण पिछले दो दिनों के दौरान आभूषण मांग में 20 प्रतिशत तक की उछाल आई है।

वैश्विक दामों से संकेत पाकर सोने के घरेलू दामों में 4 सितंबर, 2019 को इसके शीर्ष स्तर 39,031 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में 3.6 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इससे उपभोक्ताओं का बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने के दाम फिसलकर 37,615 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए जो दो महीने का सबसे निचला स्तर था और इसके बाद बुधवार को दाम मामूली सुधार के साथ 37,641 रुपये प्रति 10 ग्राम और गुरुवार को 37,778 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए।

बेंचमार्क लंदन हाजिर बाजार में सोने के दाम 4 सितंबर के हालिया शीर्ष स्तर 1,553 प्रति औंस पर जाने के बाद मंगवार को 5.7 प्रतिशत तक गिरकर 1,464 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि तब से लंदन में सोने के दाम मामूली रूप से सुधकर 1,480 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ चुके हैं।

सोने की कीमत

दिन	कीमत
29 नवंबर	37,867
2 दिसंबर	37,827
3 दिसंबर	38,111
4 दिसंबर	38,184
5 दिसंबर	38,028
6 दिसंबर	38,022
9 दिसंबर	37,648
10 दिसंबर	37,615
11 दिसंबर	37,641
12 दिसंबर	37,778

स्रोत- आईबीजेए
संकलन- बीएस रिसर्च

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन और चेन्नई स्थित खुदरा आभूषण विक्रेता एनएसी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक अनंत पद्मनाभन ने कहा कि सोने की कीमत में इस गिरावट ने भारत में आभूषणों की मांग में फिर से जान डाल दी है क्योंकि उपभोक्ता इस साल जुलाई में सराफा की कीमतों में तेजी आने के बाद से सुधार का इंतजार कर रहे थे। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ पिछले दो दिनों के दौरान आभूषण बिक्री में भी कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोने के दामों के तेज इजाफा होने की वजह से इस साल अब तक देश में आभूषण मांग नरम रही है। जुलाई के बाद से, जब सोने की कीमतों ने बढ़ना शुरू किया था, उपभोक्ता 'देखो और इंतजार करो' वाली स्थिति में थे। मई के आखिर से सितंबर तक की अवधि के दौरान सोने की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।

मुंबई में प्रसिद्ध जवेरी बाजार के खुदरा आभूषण विक्रेता उम्मेदमल तिलोकचंद जवेरी के निदेशक कुमार जैन ने कहा कि आभूषण विक्रेताओं ने इस साल जुलाई के बाद से, जब सोने दाम बढ़ना शुरू हुए थे, पहली बार ऐसा सुधार देखा है। इस साल रिकॉर्ड स्तर पर अधिक संख्या में होने वाले शादी-विवाह कार्यक्रम और नव वर्ष तथा क्रिसमस जैसे त्योहारों के लिए उपभोक्ता अपने आभूषणों की बुकिंग कराने के लिए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने आभूषणों की मांग में तेज वृद्धि देखी है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) द्वारा एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि जुलाई-सितंबर 2019 के दौरान देश में आभूषणों की मांग में 32 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है और यह फिसलकर 101.6 टन रह गई है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान मांग 148.8 टन थी। डब्ल्यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से सितंबर 2019 के दौरान आभूषणों की कुल मांग में 5.3 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और यह गिरकर 395.6 टन रह गई है।

कॉफी के दाम 10 प्रतिशत बढ़े

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 दिसंबर

कॉफी वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक कमी के अनुमानों के बीच वैश्विक स्तर पर कॉफी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में इसी के अनुरूप दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्पादकों का कहना है कि जहां एक ओर अरेबिका के दाम उत्पादन लागत के बराबर ही हैं, वहीं दूसरी ओर रोबस्टा के दाम उत्पादन लागत की तुलना में 10-12 प्रतिशत ज्यादा हैं। कॉफी वर्ष 2019-20 के दौरान 5,02,000 बोरों की कमी रहने के कारण दामों में तेजी रहने की उम्मीद है।

पिछले 12 महीनों के दौरान नवंबर में पहली बार ऐसा हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन (आईसीओ) का संयुक्त संकेतक लगातार प्रति पॉउंड 100 सेंट से अधिक रहा है। नवंबर की शुरुआत में संयुक्त संकेतक के दैनिक दाम प्रति पॉउंड 102.74 सेंट थे जो महीने के आखिर में 111.77 सेंट के स्तर पर बंद होने से पहले 25 नवंबर, 2019 को बढ़कर प्रति पॉउंड 111.86 सेंट हो गए। वर्ष 2019 में मध्य अक्टूबर से दैनिक दामों में तेजी का रुख रहा है और एक महीना पहले के मुकाबले नवंबर में 10.1 प्रतिशत बढ़कर औसतन 107.23 सेंट हो गए।

■ आईसीओ ने बरकरार रखा कॉफी वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक आपूर्ति में कुछ कमी आने का अपना शुरुआती पूर्वानुमान

अक्टूबर 2019 में कॉफी का वैश्विक निर्यात पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 13.4 प्रतिशत तक घटकर 89.1 लाख बोरे रह गया। मौसम के प्रतिकूल स्वरूप और लंबे समय तक कम रह अंतरराष्ट्रीय दामों सहित विभिन्न कारणों से सभी क्षेत्रों की खेपों में गिरावट आई है। कर्नाटक उत्पादक संघ के सदस्य और कर्नाटक के उत्पादक रोहन कोलैको का कहना है कि अरेबिका के प्रचलित दाम उत्पादन लागत के बराबर ही हैं, जबकि रोबस्टा के दाम उत्पादन लागत के मुकाबले 10 से 12 प्रतिशत अधिक हैं। देश के कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का योगदान तकरीबन 70 प्रतिशत रहता है।

अक्टूबर 2019 में कुल वैश्विक निर्यात 89.1 लाख बोरे रहा जो मासिक रूप में सितंबर 2017 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत और अक्टूबर 2017 की तुलना में 2.4 प्रतिशत गिरावट दिखाता है। ब्राजील को किए जाने वाले निर्यात में कमी इस गिरावट का मुख्य कारण थी। भारत समेत एशिया से किए जाने वले निर्यात में अक्टूबर के दौरान 23.5 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

रोबस्टा का निर्यात 21.6 प्रतिशत गिरकर 28.2 लाख बोरे और अरेबिका का निर्यात नौ प्रतिशत गिरकर 60.8 लाख बोरे रह गया। अक्टूबर 2019 में भारत का कॉफी निर्यात 3,50,000 बोरे रहने का अनुमान है जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 2.5 प्रतिशत और अक्टूबर 2017 के मुकाबले 22 प्रतिशत कम रहा।

जनवरी से नवंबर (27 नवंबर तक) 2019 के दौरान मूल्य के हिसाब से कॉफी का निर्यात (जिसमें दोबारा किया जाने वाला निर्यात भी शामिल है) 74.055 करोड़ डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले 78.665 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। इस तरह इसमें 5.77 प्रतिशत की गिरावट आई।

आईसीओ ने कॉफी वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक स्तर पर करीब 5,02,000 बोरों की कमी रहने का अपना शुरुआती पूर्वानुमान बरकरार रखा है। इससे आगे चलकर दामों पर दबाव बन सकता है। अनुमान लगाया गया है कि दिसंबर में अरेबिका के दाम प्रति पॉउंड 121.50 सेंट के स्तर पर और मई 2020 तक प्रति पॉउंड 124.25 सेंट तक जा सकते हैं। मई 2020 तक रोबस्टा के दाम प्रति टन 1,424 डॉलर हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 12	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,751.5	-1.3	1,905.7	-3.8
Copper	6,083.0	4.1	6,451.2	4.1
Nickel	13,535.0	-25.6	14,610.4	-20.4
Lead	1,903.0	-8.8	2,188.0	5.9
Tin	17,425.0	-0.2	18,210.1	-1.9
Zinc	2,222.0	-5.7	2,597.4	-1.7
Gold ($/ounce)	1,474.9*	-1.6	1,658.7	0.7
Silver ($/ounce)	16.9*	-6.7	19.2	-6.0
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	65.5*	7.8	64.4	7.3
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-11.3	2.3	-11.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	183.1	10.8	300.7	5.3
Maize	181.5*	1.1	324.1	12.6
Sugar	352.1*	11.1	484.5	-0.4
Palm oil	715.0	33.6	1,120.0	27.9
Rubber	1,607.0*	4.8	1,863.4	-3.9
Coffee Robusta	1,428.0*	8.7	1,898.6	-8.1
Cotton	1,454.8	6.0	1,582.7	-3.1

* As on Dec 12, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	16.7	13100
Oil and Oilseeds	109.4	81083
Spices	0.0	14
Metal(Dec 11)		
Metal- non ferrous	6749.9	62437
Metal- precious	7017.2	502
Oil and gas(Dec 11)		
Gas	1951.7	44171
Oil	13563.2	2167

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	128.5	104055
Grains	92.4	104010
Oil and Oilseeds	711.6	499475
Others	77.7	68155
Pulses	87.7	57875
Spices	105.6	33335

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Nickel (Dec 31)	1014.3	2.3
Crude Palm Oil (Dec 31)	724.0	1.0
Silver Mini (Feb 28)	43853.0	0.7
Silver Micro (Feb 28)	43856.0	0.7
Silver (Mar 05)	43825.0	0.7
Copper (Dec 31)	442.1	0.7
Kapas (Apr 30)	1086.5	0.6
Losers (* % Change)		
Crude Oil (Dec 18)	4156.0	-0.9
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4157.0	-0.9
Zinc Mini (Dec 31)	181.3	-0.4
Zinc (Dec 31)	181.3	-0.2
Natural Gas (Dec 26)	160.5	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6200.0	3.2
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2038.0	2.0
Soyabean Indore (Dec 20)	4230.0	1.6
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4248.0	1.3
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4446.0	1.0
Coriander-Kota (Dec 20)	7057.0	1.0
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	859.0	0.8
Jeera Unjha (Dec 20)	16580.0	0.8
Chana-Bikaner (Dec 20)	4357.0	0.6
Barley Jaipur (Apr 20)	1718.0	0.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1086.0	0.5
Losers (* % Change)		
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7149.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	2.7
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3051.1	2.4
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19060.0	2.0
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3853.0	1.7
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	43856.0	0.5
Silver Ahm (Mar 05)	43825.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1301.4	-7.6
Alumini-Mumbai (Dec 31)	132.6	-4.8
Aluminium Mum (Dec 31)	132.7	-4.7
Copper Mum (Dec 31)	442.1	-2.1
Nickel Mumbai (Dec 31)	1014.3	-1.0
Zinc Mumbai (Dec 31)	181.3	-0.5

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6200.0	2.4
Jeera Unjha (Dec 20)	16580.0	1.2
Coriander-Kota (Dec 20)	7057.0	0.7
Soy Bean Indore (Dec 20)	4230.0	0.6
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18660.0	0.2
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3205.0	0.2
Moong-Merta City (Dec 20)	6690.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7149.0	-2.0
Maize-Sangli (Dec 20)	2027.0	-0.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2113.0	-0.4
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	733.5	-0.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	100......(100)
Aluminium ingots /kg	135......(135)
Brass sheet cutting /kg	319......(317)
Brass utensil scraps/kg	301......(300)
Copper heavy scrap /kg	423......(420)
Copper utensil scraps/kg	398......(397)
Copper wire bar /kg	457......(456)
Lead ingots /kg	155......(155)
Nickel Cathodes /kg	1035......(1010)
Tin slabs /kg	1290......(1295)
Zinc slabs /kg	184......(184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10686......(10742)
DCH - 32 /Qtl	11417......(11473)
Jaydhar /Qtl	10067......(10067)
Shankar- 6 /Qtl	11220......(11276)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	900......(892)
Castor Comm /10kg	890......(882)
Ricebran oil/10kg	760......(760)
Groundnut oil /10kg	1050......(1050)
Linseed oil /10kg	865......(805)
Karanji /10kg	780......(780)
Palm oil /10kg	803......(807)
Sunflower exp ref /10kg	855......(850)
Sunflower oil exp /10kg	810......(810)
Soyabean ref / 10kg	850......(855)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3292-3572 ......(3292-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	59.11......(58.76)
Brent Crude (UK)	65.63......(65.16)
Brent Crude (WTI)	58.76......(58.76)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.28......(2.24)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	268.27......(255.74)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37778......(37641)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	37930......(37792)
Silver.999/ kg	43730......(43260)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18630.60	18620.65
Alumini-Mumbai (M)	1 K	137.75	139.25
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1950.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2109.65	2120.45
Brass-Jamnagar (M)	1 K	314.35	315.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3033.00	3000.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4231.65	4231.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4200.00	4212.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4250.00	4276.55
Chana Delhi (N)	1 Q	4450.00	4450.00
Chana-Akola (N)	X	4350.00	4350.00
Coriander-Gondal (N)	X	6800.00	6750.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6921.25	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7042.35	7006.10
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2098.20	2106.30
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2026.65	2034.85
Cotton-Kadi (N)	1 B	18513.10	18546.30
CPO-Kandla (M)	10 K	717.50	720.60
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	731.25	735.55
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	877.45	876.30
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1531.80	1527.60
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3436.25	3433.05
Gold Ahm (M)	10 G	37631.00	37763.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30226.00	30332.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3778.00	3789.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7237.50	7293.20
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3926.50	3931.80
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3850.00	3850.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1100.90	1140.50
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.55	93.75
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16700.00	17200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16387.50	16390.90
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1016.20	1017.45
Kapas-Rajkot (N)	X	1022.05	1017.40
Lead Mum (M)	1 K	155.20	154.25
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1991.25	2000.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2292.65	2324.00
Maize-Erode (N)	X	2045.40	2071.50
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Maize-Sangli (N)	X	2023.35	2035.85
Moong-Merta City (N)	1 Q	6680.55	6680.55
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4623.70	4630.15
Nickel Mumbai (M)	1 K	1002.80	1025.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3187.00	3178.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	353.00	355.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35360.00	35220.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	813.00	813.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2036.95	2036.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	791.50	793.40
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	852.15	852.70
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	853.00	852.55
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	868.75	872.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13200.00	13200.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43214.00	43640.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4174.00	4205.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4141.00	4090.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4242.00	4279.90
Soy Bean-Akola (N)	X	4206.00	4244.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33889.00	34000.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	851.00	852.20
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27900.00	27800.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28700.00	28600.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25800.00	25740.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3331.20	3336.95
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3293.75	3288.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3457.15	3433.35
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3260.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3132.00	3129.55
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5966.65	6054.70
Wheat Delhi (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2126.20	2150.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2082.50	2062.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2180.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5100.00	4925.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	182.65	182.20

* as on Dec 11, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19020, 19110, 18950, 19060	1127	209	8695
Jan 31	19150, 19250, 19100, 19210	306	66	3469
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	1994, 2057, 1988, 2038	7590	389	20090
Jan 20	2000, 2047, 1986, 2041	44340	2841	50620
Feb 20	2023, 2065, 2012, 2061	4870	463	26720
Mar 20	2046, 2085, 2044, 2065	890	83	2570
Apr 20	2070, 2070, 2070, 2070	10	1	20
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1081, 1088, 1079.5, 1086.5	120	30	600
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1080, 1088.5, 1079.5, 1086	528	318	4035
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1718, 1718, 1718, 1718	30	2	950
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3952, 3962, 3930, 3948	3120	225	12860
Jan 20	4000, 4026, 3984, 4002	19140	2198	80505
Feb 20	4036, 4064, 4028, 4046	830	82	4140
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4210, 4252, 4200, 4248	2535	272	17925
Jan 20	4242, 4288, 4230, 4282	6440	678	26975
Feb 20	4230, 4310, 4210, 4262	435	66	3910
Mar 20	4236, 4282, 4236, 4268	55	11	4030
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	718, 724.4, 717.3, 724	5400	426	31860
Jan 31	719.9, 725.8, 718, 725.3	6610	400	44990
Feb 28	715.5, 722.9, 715.5, 721.1	500	36	3910
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1295, 1307, 1293.3, 1301.4	132.12	321	267.12
Jan 31	1308.5, 1315.5, 1306, 1312.2	13.68	35	55.08
May 29	1322.2, 1322.2, 1322.2, 1322.2	0.36	1	0.36
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4395, 4448, 4395, 4446	4920	274	5620
Jan 20	4417, 4473, 4417, 4468	10380	692	14350
Feb 20	4398, 4438, 4388, 4400	220	11	320
Apr 20	4350, 4390, 4340, 4358	380	20	2020
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	854, 859.4, 851.6, 859	4445	261	13560
Jan 20	855.6, 862.2, 852.6, 861.6	16825	1679	50965
Feb 20	851.2, 859.2, 850, 857.8	2020	190	19545
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4156, 4236, 4148, 4230	13390	1462	18405
Jan 20	4206, 4276, 4186, 4266	59570	5993	178915
Feb 20	4228, 4300, 4218, 4292	15115	1984	107340
Mar 20	4260, 4322, 4252, 4316	5220	799	33610
Apr 20	4280, 4330, 4276, 4306	1195	195	1885
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7198, 7203, 7130, 7149	2025	156	3185
Jan 20	7286, 7309, 7223, 7250	7645	1002	61760
Feb 20	7391, 7405, 7330, 7355	1035	135	3100
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4359, 4390, 4340, 4357	2160	186	9750
Jan 20	4344, 4390, 4340, 4363	16720	1285	44250
Mar 20	4313, 4325, 4306, 4321	1230	104	3220
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3050, 3050, 3050, 3050	0.1	1	11.8
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7070, 7145, 7000, 7057	1270	123	4250
Jan 20	6698, 6871, 6570, 6607	4900	456	7820
Apr 20	7120, 7175, 6899, 6912	1850	169	3950
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16450, 16585, 16450, 16580	15	5	366
Jan 20	15860, 15900, 15780, 15820	1038	256	2844
Mar 20	15850, 15850, 15810, 15810	30	10	198
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6060, 6248, 6060, 6200	600	113	4630
Mar 20	6218, 6338, 6210, 6278	3690	644	6910
Apr 20	6232, 6318, 6182, 6206	1065	195	2325
May 20	6312, 6312, 6312, 6312	10	1	15

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 133.1, 132.4, 133	3095	507	8075
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 133.1, 132.3, 132.95	1419	1198	3117
Jan 31	132.7, 133.35, 132.7, 133.3	48	47	713
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441.8, 442.7, 440.2, 441.3	14580	4845	14582.5
Jan 31	446.85, 446.9, 444.75, 445.65	260	102	1487.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.8, 154.15, 153.65, 153.9	6705	1144	5400
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.65, 154.15, 153.65, 153.9	2351	2031	2323
Jan 31	153.15, 153.2, 152.9, 153.1	85	73	849
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1015.4, 1023, 1005, 1015.9	17709	10457	3211.5
Jan 31	1012.1, 1018.4, 1002, 1012	318	207	324
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.9, 183.3, 181.65, 182.15	23735	3833	18105
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	181.65, 183.1, 181.65, 182.15	8129	6237	7660
Jan 31	180, 180.65, 179.6, 180.1	1368	918	6167
Feb 28	180.1, 180.1, 180.05, 180.1	2	2	11
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37770, 37820, 37631, 37801	5.78	4708	15.97
Apr 03	37812, 37883, 37715, 37876	0.25	190	2.6
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30585, 30585, 30458, 30501	0	97	0
Jan 31	30474, 30474, 30381, 30416	0	42	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37749, 37815, 37640, 37789	0.65	5487	0.88
Feb 05	37763, 37823, 37650, 37805	0.15	1118	0.28
Mar 05	37790, 37826, 37700, 37781	0	7	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3856, 3860, 3854, 3859	0	415	0.01
Jan 31	3830, 3839, 3830, 3837	0	101	0
Feb 28	3744, 3835, 3744, 3781	0	10	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43969, 44059, 43804, 44010	213.06	5786	406.32
May 05	44555, 44565, 44307, 44478	0.63	19	6.06
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43900, 44076, 43844, 44036	18.03	12409	35.12
Apr 30	44488, 44566, 44339, 44529	0.79	631	1.68
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43910, 44092, 43841, 44031	57.29	9015	62.48
Apr 30	44525, 44566, 44342, 44540	0.76	146	1.55

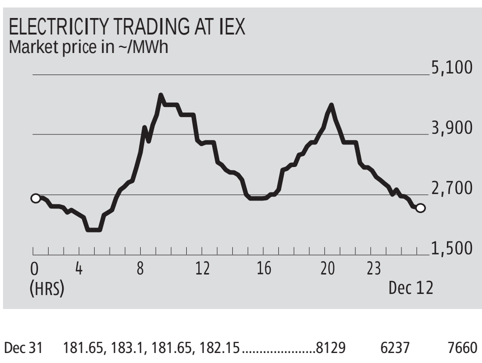

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	160, 162.7, 159.2, 162.1	47090mb	20617	33925mb
Jan 28	160.7, 163.2, 160, 162.5	3601mb	1806	11799mb
Feb 25	158.7, 160.9, 158.4, 160.1	333mb	261	3003mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4161, 4187, 4152, 4180	7472bl	37413	3306bl
Jan 17	4166, 4190, 4158, 4183	299bl	2113	294bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4153, 4186, 4153, 4180	1631bl	64582	688bl

सायं सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19030, 19090, 19000, 19020	2075	345	8822
Jan 31	19180, 19250, 19150, 19190	846	147	3350
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1083, 1085.5, 1079.5, 1080.5	264	51	596
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1084, 1085.5, 1078, 1081	795	402	4045
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	720.1, 725.9, 715.2, 717.8	20380	1415	32230
Jan 31	719.4, 727.6, 716.2, 718.8	21300	1257	43950
Feb 28	715.7, 724, 712.8, 714.1	2280	191	4010
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	855, 858.8, 850.4, 852.4	7680	771	15380
Jan 20	855, 859.8, 851, 854	20685	2318	51610
Feb 20	848, 857, 847.8, 852.4	1330	178	18830

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.3, 132.8, 132.15, 132.65	6880	1046	7550
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.15, 132.75, 132.15, 132.6	2510	2125	2883
Jan 31	133.05, 133.2, 132.7, 133.1	133	129	704
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	438.95, 442.75, 438.55, 442.05	36180	11476	13612.5
Jan 31	443.35, 447.1, 443.2, 446.4	1047.5	394	1482.5
Feb 28	447.9, 449.7, 445, 448.3	17.5	6	35
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 154.1, 153.4, 153.85	18880	3116	4055
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 154.05, 153.4, 153.85	6729	5385	1796
Jan 31	152.75, 153.1, 152.45, 152.85	418	306	824
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	992.6, 1016.2, 991.2, 1014.3	31600.5	18772	1909.5
Jan 31	989, 1011, 986.2, 1009.6	538.5	348	318
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.8, 182.8, 181.05, 181.25	51440	8476	15145
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.3, 182.8, 181.05, 181.25	20580	14699	6318
Jan 31	180.4, 181.05, 179.25, 179.45	2885	1515	5795
Feb 28	180.15, 180.5, 180.15, 180.25	4	4	9
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37580, 37738, 37520, 37699	9.23	7954	15.74
Apr 03	37650, 37806, 37590, 37784	0.23	225	2.4
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30415, 30575, 30387, 30455	0	277	0
Jan 31	30391, 30420, 30357, 30370	0	53	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37602, 37741, 37554, 37693	1.09	9049	0.8
Feb 05	37623, 37760, 37557, 37712	0.24	1746	0.31
Mar 05	37635, 37740, 37595, 37675	0	9	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3853, 3856, 3848, 3853	0	766	0.01
Jan 31	3825, 3833, 3823, 3830	0	250	0
Feb 28	3827, 3827, 3819, 3821	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43501, 43964, 43406, 43825	490.74	13546	384.63
May 05	44016, 44355, 43950, 44328	0.81	26	5.94
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43600, 43988, 43441, 43856	48.02	30272	33.13
Apr 30	44060, 44476, 43963, 44343	1.4	1128	1.64
Jun 30	44800, 44800, 44800, 44800	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43527, 43977, 43435, 43853	133.89	20615	55.77
Apr 30	44052, 44483, 43972, 44342	1.3	245	1.44

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	161.8, 163.4, 159.9, 160.5	112234mb	49146	30018mb
Jan 28	162.3, 163.7, 160.8, 161.3	7665mb	4036	11245mb
Feb 25	160.3, 161.3, 158.9, 159.3	761mb	563	2909mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4175, 4192, 4115, 4156	26091bl	128768	1607bl
Jan 17	4190, 4195, 4120, 4160	848bl	6276	215bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4187, 4192, 4114, 4157	5667bl	220133	344bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

नई दिल्ली | 13 दिसंबर 2019 शुक्रवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

प्रदर्शन के बीच छावनी बन गया असम

असम में हजारों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया, कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है

असम में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ गुरुवार को हजारों की संख्या में लोगों ने गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरे। राज्य के विभिन्न इलाकों में सेना की पांच टुकड़ियां तैनात हैं और वे गुवाहाटी, तिनसुकिया, जोरहाट और डिब्रूगढ़ में फ्लैग मार्च कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल दो व्यक्तियों की गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस को लालुंग गांव में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलानी पड़ीं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनपर पथराव किया। सीएबी बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

छात्र संगठन आसू और किसान संगठन केएमएसएस के आह्वान पर गुवाहाटी के लताशील मैदान में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया फोटोः पीटीआई

मुख्यमंत्री की वीडियो अपील

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य के लोगों से एक वीडियो अपील में गुरुवार को कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असम समझौते की धारा छह की भावना के अनुरूप उनकी राजनीतिक, भाषायी, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

इस बीच असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि गुरुवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार की शाम सात बजे इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं।

असम की उड़ानें रद्द

विरोध प्रदर्शन के कारण कई विमानन कंपनियों ने राज्य के कई शहरों की उड़ानें गुरुवार को रद्द कर दी। उड़ानें रद्द करने वाली विमानन कंपनियों में इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और स्पाइसजेट शामिल हैं। गोएयर और एयर एशिया ने यात्रा की तारीख बदलने पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा कि असम में विरोध प्रदर्शनों की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ की उड़ानें रद्द की गई हैं। कंपनी ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की उड़ानों के यात्रियों के लिए 13 दिसंबर तक टिकट रद्द करने या यात्रा की तिथि बदलने के लिए शुल्क समाप्त कर दिया है। रेलवे ने असम और त्रिपुरा आने-जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों को स्थगित कर दिया और लंबी दूरी वाली ट्रेनों को गुवाहाटी में ही रोका जा रहा है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला बुधवार रात में लिया गया जिसके बाद कई यात्री कामाख्या और गुवाहाटी में फंस गए।

पुलिस महकमे में बदलाव

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस महकमे में कुछ बदलाव किए हैं। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त और कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया। आयुक्त और सचिव (गृह एवं राजनीति) आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि गुवाहाटी के पुलिस प्रमुख दीपक कुमार को हटाकर उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। गुप्ता इससे पहले एसपीजी में तैनात थे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) मुकेश अग्रवाल का स्थानांतरण कर (सीआईडी बनाया गया है।

पूर्वोत्तर में फैलाया जा रहा है भ्रमः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को पारित होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही हिंसा पर गुरुवार को शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग, विशेषकर युवा उन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। असमिया और अंग्रेजी भाषा में किए कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से और केंद्र सरकार धारा छह की भावना के अनुसार लोगों को राजनीतिक, भाषायी, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा की पूर्वोत्तर के लोगों की संस्कृति, विरासत, भाषा, परंपरा और जीवनचर्या को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस और उसके सहयोगियों के भ्रम जाल में ना फंसें क्योंकि भाजपा पूर्वोत्तर को देश की वृद्धि का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

झारखंड विधानसभा चुनावों के 16 दिसंबर को होने वाले चौथे चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पूर्वोत्तर में रेल लाइनें, सड़कें, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। लोगों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।' मोदी ने दोहराया कि पूर्वोत्तर के कई इलाकों में आग लगाने की कोशिश हो रही है जबकि पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। मोदी ने कहा कि भाजपा ने आपसे वादा किया था कि पूरे देश में यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी एक संविधान और भारतीय कानून लागू करेंगे, उसे हमने अनुच्छेद 370 खत्म कर अपना वादा पूरा किया है। *बीएस/एजेंसियां*

उत्तर-पूर्व को बनाएं ब्रांडः विश्व बैंक

ईशिता आयान दत्त

- रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्वोत्तर की क्षमताओं का लाभ लेने के लिए बनाया जाए 'ब्रांड उत्तर-पूर्व'
- पूर्वोत्तर की मदद से फल निर्यात में बेहतर हो सकती है भारत की स्थिति
- चिकित्सा पर्यटन, स्वस्थ जीवन आदि मानकों को किया जा सकता है शामिल

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर भारत की क्षमताओं का लाभ लेने के लिए इसे एक ब्रांड के तौर पर पेश करना चाहिए। स्वस्थ जीवन, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी, सेवा तत्परता और अन्य मानकों के आधार पर उत्तर-पूर्व को ब्रांड बनाया जा सकता है।

रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने से उत्तर-पूर्व क्षेत्र से होने वाले उत्पादन और क्षेत्र विशेष संबंधी गतिविधियों से जुड़े क्लस्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, यहां की उत्पाद श्रृंखला वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने में योगदान दे सकती हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, नीतिगत हस्तक्षेप करके उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वैश्विक रुझानों द्वारा पैदा हुए अवसरों को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे 'ब्रांड नॉर्थ ईस्ट' बनाने में मदद मिलेगी।

इसमें दिए गए दूसरे सुझावों के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए निजी क्षेत्र का लाभ उठाना, कनेक्टिविटी सेवाओं को बेहतर करना और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए मांग को बढ़ावा देना होगा।

रिपोर्ट में बदलती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आपूर्ति आधार को फिर से खड़ा करने का आह्वान किया गया है। उदाहरण के लिए, ऑर्गेनिक सामान उत्पादन में अपनी विशिष्टता के साथ पूर्वोत्तर ताजे फल एवं सब्जियों के क्षेत्र में, विशेषकर उपभोक्ताओं की बदलती वरीयताओं के दौर में वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकता है।

भारत वैश्विक स्तर पर फलों एवं सब्जियों का प्रमुख उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है लेकिन वैश्विक स्तर पर फल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.5 प्रतिशत है।

विश्व बैंक के संयोजक एवं प्रमुख अर्थशास्त्री संजय कथूरिया ने कहा, 'अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वोत्तर में कृषि और सेवा क्षेत्रों में बहुत अधिक क्षमता है। पूर्वोत्तर में इस लाभ की स्थिति का दोहन फलों एवं सब्जियों, मसालों, बांस तथा चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहन देकर उठाया जा सकता है।' कथूरिया ने कहा कि इस क्षेत्रों को प्रोत्साहन के लिए पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए और साथ ही क्षेत्र के लिए एक ब्रांड बनाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने रद्द किया भारत दौरा

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि गुवाहाटी में होने वाले भारत-जापान शिखर सम्मेलन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन ने गुरुवार से शुरू होने वाला भारत का अपना तीन दिवसीय दौरा रद्द कर दिया है। राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय द्वारा पहले जारी की गई एक सूचना के अनुसार मोमिन को गुरुवार शाम भारत पहुंचना था। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के पारित होने से पैदा हुए हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द की है। हालांकि ढाका में जारी एक बयान में मोमिन ने कहा कि उन्हें अपनी व्यस्तताओं के चलते भारत की यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने यह कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान धार्मिक उत्पीड़न हुआ। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत-जापान शिखर सम्मेलन 15-17 से गुवाहाटी में होगा या नहीं, इस पर उनके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, 'मुझे भारत का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि मुझे बुद्धिजीवी दिवस और विजय दिवस में भाग लेना है। इसके अलावा हमारे राज्य मंत्री मैड्रिड में है और विदेश सचिव हेग में है।' बांग्लादेश सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में व्यस्तताओं के कारण विदेश मंत्री को भारत दौरा रद्द करना पड़ा। नागरिकता (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हुआ था। अफगानिस्तान, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

इमरान का बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुनियोजित तरीके से हिंदू सर्वोच्चवादी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है और इससे पहले कि देर हो जाए, विश्व को जरूर ही कदम उठाना चाहिए। खान ने सिलसिलेवार ट्वीट में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक का जिक्र किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा, 'परमाणु खतरे के तहत पाकिस्तान को धमकियों के साथ यह एजेंडा खून-खराबे की ओर ले जाएगा और दुनिया के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे।' इमरान की इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टीका टिप्पणी करने के बजाय (पाकिस्तान में) अल्पसंख्यकों के साथ अपने बरताव पर ध्यान देना चाहिए।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया, 'हमने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, अन्य हितधारकों से संपर्क किया है, उम्मीद है कि वे हमारी स्थिति को समझेंगे।' *एजेंसियां*

असम में क्यों हो रहा है विधेयक का विरोध

असमिया समुदाय को डर है कि बांग्लाभाषियों की बढ़ती आबादी से बदलेगा राज्य का सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप

साई मनीष

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को लेकर पूर्वोत्तर बंटा हुआ है। खासकर असम में इसका भारी विरोध हो रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के मोदी सरकार के फैसले का असम में छात्र, राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। असमिया समुदाय को लगता है कि बांग्लाभाषियों की बढ़ती आबादी के कारण उनका सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में है।

असमिया लोगों को सीएबी से क्या खतरा है? इसके जवाब का एक हिस्सा पड़ोसी देश बांग्लादेश से ताल्लुक रखता है जहां से पिछले कई वर्षों के दौरान लाखों लोग भारत आए हैं। बांग्लादेश में 1951 में बांग्लाभाषी हिंदुओं की आबादी 22 फीसदी थी। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद वहां से बड़ी संख्या में लोग असम आए। बांग्लादेश की सीमा असम से लगती है। बांग्लादेश में 1981 में करीब एक करोड़ यानी 12 फीसदी हिंदू थे। लेकिन 2011 तक 30 वर्षों के दौरान वहां हिंदुओं की आबादी महज 10 लाख बढ़ी। आज बांग्लादेश की आबादी में केवल 8.5 फीसदी हिंदू हैं। इन 30 वर्षों के दौरान वहां मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ से अधिक बढ़ी। बांग्लादेश में हिंदू आबादी मुसलमानों से अधिक गरीब है, उनकी प्रजनन दर कम है और उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम है। पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण हिंदुओं का पलायन हुआ जबकि बांग्लादेश से पलायन के आर्थिक कारण थे। कई वर्षों के दौरान हिंदू और मुसलमान बांग्लादेश से असम आए। बेल्जियम की संस्था इंटरनैशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ने 21 वर्षों के पलायन के आंकड़ों का अध्ययन किया। इनमें से 18 वर्षों के दौरान बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक थी।

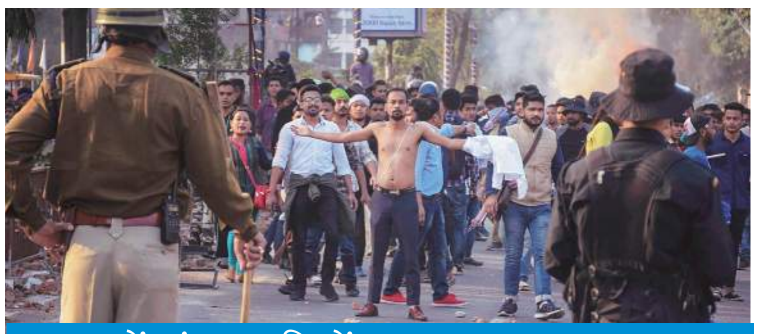

असम में बांग्लाभाषियों का पलायन

वर्ष	असमिया भाषी	बांग्लाभाषी	असमिया आबादी	बांग्ला आबादी
1961	**68** लाख	**21** लाख	**57** फीसदी	**18** फीसदी
1991	**1.29** करोड़	**49** लाख	**58** फीसदी	**22** फीसदी
2011	**1.51** करोड़	**90** लाख	**48** फीसदी	**29** फीसदी

स्रोतः भारतीय जनगणना

बांग्लादेश की घट रही हिंदू आबादी

वर्ष	हिंदू	हिंदू आबादी का प्रतिशत
1951	**97.2** लाख	**22** फीसदी
1981	**1.107** करोड़	**12.3** फीसदी
2011	**1.273** करोड़	**8.5** फीसदी

स्रोतः आईयूएपीएस

अध्ययन के मुताबिक बांग्लाभाषी हिंदू और मुसलमानों की 86 फीसदी आबादी 1992 से 2004 के दौरान भारत आई।

बांग्लादेश से होने वाले इस पलायन के कारण असम की जनांकीय स्थिति में भी भारी बदलाव हुआ। 1961 में राज्य में 70 लाख असमिया भाषी लोग थे जबकि बांग्ला बोलने वालों की आबादी 20 लाख थी। 2011 में बांग्लाभाषियों की आबादी करीब चार गुना बढ़कर 90 लाख पहुंच गई जबकि इस दौरान असमिया बोलने वाले लोगों की जनसंख्या केवल दोगुना बढ़कर 1.5 करोड़ पहुंची। यानी बांग्लादेश में बांग्लाभाषी हिंदुओं की संख्या में कमी आ रही है जबकि असम में उनकी आबादी बढ़ रही है। असम में 1991 से अजीबोगरीब घटनाक्रम दिखाई देता है।

असम में 1991 से 2011 के बीच बांग्लाभाषियों की संख्या हिंदुओं की कुल आबादी से थोड़ा ज्यादा और मुसलमानों की आबादी से थोड़ा कम बढ़ी। इस दौरान असमिया बोलने वाले लोगों की संख्या हिंदू या मुसलमान आबादी से आधी बढ़ी। 1991 से 2011 तक असमिया भाषी लोगों की संख्या केवल 20 लाख बढ़ी। इस दौरान बांग्लाभाषी हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी करीब 40 लाख बढ़ी। यानी असम में सबसे ज्यादा बांग्लाभाषियों की ही आबादी बढ़ रही है और यही वजह है कि असमिया समुदाय को अपनी सामाजिक-संस्कृति पहचान खोने की आशंका है।

असमिया समुदाय को डर है कि सीएबी के कारण उसका सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। असम में बांग्ला भाषा और संस्कृति हावी हो रही है। मोदी सरकार ने सीएबी में शरणार्थियों के लिए नागरिकता पाने की कट ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 रखी है। यह 1985 के असम समझौते को निरस्त कर देगा जिसमें कट ऑफ तिथि 25 मार्च, 1971 रखी गई थी। सीएबी को संसद की मंजूरी असम समझौते को निरस्त कर देगी और राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के डर से दूसरे राज्यों को पलायन कर चुके या एनआरसी से बाहर रह गए बांग्लाभाषी भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। इस तरह उन्हें असम में रहने, काम करने और परिवार पालने का अधिकार मिलेगा जहां उनका मजबूत सामुदायिक तानाबाना है।

असम में चल रहा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक के बांग्ला विरोधी आंदोलन की याद दिलाता है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने 1979 से 1985 तक चले उस आंदोलन की अगुआई की थी और इस बार भी सीएबी के खिलाफ वही सबसे अधिक मुखर है। 1980 के दशक में बांग्ला विरोधी आंदोलन में व्यापक हिंसा हुई थी जिसमें नेली और खोइराबारी नरसंहार भी शामिल है। असम में 1960 के दशक से बांग्ला विरोधी आंदोलन का इतिहास रहा है। 1960 में शुरू हुआ कुख्यात 'बोंगाल खेड़ा' आंदोलन में बांग्लाभाषी हिंदुओं के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे और बांग्ला भाषा के स्कूलों को असमिया में बदला गया था। असम में जिस तरह हर दिन विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर मोदी सरकार के सीएबी से राज्य में बांग्ला विरोधी हिंसा का दौर फिर से शुरू होने की आशंका है।